राम चंद गुप्ता, जे.

भारत संघ - **अपीलकर्ता**

बनाम

शाम सुंदर दास और अन्य- **प्रतिवादी**

1983 का आरएसए नंबर 1999

9 मई. 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—सीमा अधिनियम, 1963—एस. 5- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971- धारा 15- भारत संघ रक्षा भूमि और उस पर मौजूद भवन को फिर से शुरू करने के लिए नोटिस जारी करता है और 30 दिनों के भीतर कब्जा देने का निर्देश देता है- भारत संघ मूल्य के रूप में चेक भी भेजता है भूमि पर खड़ी संरचना - वादी नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद भी संपत्ति का कब्जा सौंपने में विफल रहे - यूओ1 1971 अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर रहा है - ट्रायल कोर्ट ने अवैध, शून्य, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ फिर से शुरू करने से संबंधित नोटिस पर रोक लगा दी है - संघ का संघ भारत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर करने में विफल रहा है - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया और इसके परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया - क्या किसी डिक्री से अपील को इस आधार पर खारिज करना कि अपील सीमा से वर्जित है, अपील में एक निर्णय है - माना गया, हां - जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर निर्णय दिया जाता है और अपील सीमा आदि के आधार पर खारिज कर दी जाती है, ऐसी बर्खास्तगी अपील की सुनवाई के बराबर होती है और अंततः योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है - यूओआई द्वारा दायर अपील को बनाए रखने योग्य माना जाता है - भारत संघ संतोषजनक ढंग से अपील दायर करने में 67 दिनों की देरी की व्याख्या करते हुए - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज करने में अवैधता की - प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश ने देरी की माफी के अनुरोध को खारिज कर दिया - ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी "पुराने अनुदान" पर संपत्ति के कब्जे में हैं। शर्तें-रेग के अनुसार। 12 सितंबर, 1836 के आदेश के 6, भारत संघ को बिना कोई कारण बताए साइट को फिर से शुरू करने का अधिकार है और केवल एक महीने का नोटिस देने की आवश्यकता है - ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि नोटिस जारी करने से पहले वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। गैरकानूनी होना - हालाँकि, वादी को भूमि पर खड़ी इमारत के अधिग्रहण के कारण उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने से पहले सुनवाई के अवसर का हकदार माना जाता है।

माना गया कि भले ही किसी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि इसे समय से पहले प्रस्तुत किया गया था, यह संहिता में प्राप्त डिक्री की परिभाषा के भीतर एक डिक्री है। इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वर्तमान नियमित दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

(पैरा 27 एवं 28)

इसके अलावा, यह माना गया कि अपील दायर करने में देरी को अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया गया है, क्योंकि फ़ाइल को रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत विभिन्न कार्यालयों में निपटाया गया था, और यह कानूनी सलाहकार (रक्षा) की राय प्राप्त करने के बाद ही किया गया था। महानिदेशक द्वारा अपील दायर करने के लिए सैन्य संपदा अधिकारी, अंबाला सर्कल, अंबाला कैंट को निर्णय से अवगत कराया गया। रक्षा भूमि और छावनियाँ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली 21 अगस्त 1980 को और अपील तैयार करने में केवल कुछ ही दिन लगे, जिसका निर्णय 30 अगस्त 1980 को हुआ। इसलिए, पता चला कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दायर आवेदन को खारिज करने में अवैधता की है। अपीलकर्ता-अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए प्रतिवादी। उक्त आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है और अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

(पैरा 34 एवं 35)

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी - वादी के साथ सख्ती से और अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि जी.जी.ओ. में उल्लिखित है। क्रमांक 179 दिनांक 12 सितंबर, 1836। वर्तमान प्रतिवादी-वादी ने अपने पूर्ववर्तियों के स्थान पर कदम रखा है। उक्त आदेश के विनियम 6 के अनुसार। भारतीय संघ को बिना कोई कारण बताए साइट को फिर से शुरू करने का अधिकार है और इसकी एकमात्र आवश्यकता एक महीने का नोटिस देना है, जो वर्तमान मामले में दिया गया है। इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर बहाली नोटिस को अवैध घोषित करने में अवैधता की है कि उक्त नोटिस जारी करने से पहले प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और प्रतिवादी-वादी को यह निर्धारित करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। मुआवज़ा. विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि प्रतिवादी-वादी द्वारा "पुराने अनुदान" की शर्तों को उचित रूप से रखा गया था, ने नोटिस को अवैध मानने में अवैधता की है।

इसके अलावा, यह माना गया कि भारत संघ की भूमि पर बनी इमारत के अधिग्रहण के कारण उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने से पहले प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं

दिया गया क्योंकि निर्माण एक अनुमेय है। इसलिए, प्रतिवादी-वादी को सुने जाने का अधिकार है, भले ही जीजी.0 में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। संख्या 179. इसलिए, इस हद तक नोटिस लगाया गया है कि यह भवन के अधिग्रहण के संबंध में देय मुआवजे को केवल रु। 64,126 को कानून की नजर में खराब कहा जा सकता है. पुनर्निर्मित भवन के मूल्य की मात्रा के निर्धारण के संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर देना प्रतिवादी-वादी का दायित्व है।

(पैरा 70 एवं 71)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—ओ. 41 आरएल.27 और एस.151-अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की गई और आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया-वादी ने कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल किया-वादी यह दिखाने में असफल रहे कि अपील पर निर्णय लेने के लिए उक्त दस्तावेज कैसे आवश्यक हैं-आवेदन खारिज किया जा रहा है योग्यता से रहित।

माना गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं-वादी द्वारा कोई क्रॉस-अपील/क्रॉस आपत्तियां दायर नहीं की गईं। बल्कि वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर अपील का प्रतिवादी-वादी ने परिसीमा के आधार पर विरोध किया था और उसे परिसीमा के आधार पर ही खारिज कर दिया गया था। अधिकांश दस्तावेज़, जिन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की गई है, कुछ अधिसूचनाओं, अधिनियमों और कुछ अन्य संपत्तियों के संबंध में कुछ निर्णयों और छावनी संपत्तियों के कुछ अन्य कब्जेदारों को जारी किए गए कुछ नोटिसों की प्रतियां हैं। अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले कोई भी दस्तावेज़ पार्टियों के बीच वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए, संहिता की धारा 151 के साथ पढ़े गए आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने के लिए उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

(पैरा 45 एवं 47)

सुश्री रंजना साही, अपीलकर्ता की ओर से वकील।

संजय मजीठिया. प्रतिवादियों के वकील शैलेन्द्र मोहन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

सी.एम. में आवेदक-प्रतिवादी के वकील एस.आई.बंसल। 2011 की संख्या 3368-69।

राम चंद गुप्ता, जे.

(1) वर्तमान नियमित द्वितीय अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:

(2) प्रतिवादी-वादी ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि उप निदेशक, सैन्य भूमि और छावनी, रक्षा मंत्रालय (एमएल एंड सी) द्वारा जारी नोटिस संख्या 1/41/एल/एल एंड सी/69 दिनांक 21 मार्च, 1975/7 अप्रैल, 1975 नई दिल्ली, बंगला नंबर 102, मॉल, अंबाला कैंट की बहाली से संबंधित, जिसकी माप 1.60 एकड़ या उसके आसपास है और इसकी सीमा इस प्रकार है:

उत्तर की ओर - सड़क मार्ग से

दक्षिण में - सर्वे नंबर 357 (बंगला नंबर 103)

पूर्व में - सड़क

पश्चिम में - सर्वेक्षण संख्या 358,

अवैध, अशक्त, शून्य और असंवैधानिक है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसलिए, उत्तरदाताओं-वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है और प्रतिवादी ने इसमें कोई अधिकार, शीर्षक या हित हासिल नहीं किया है।

(3) यह कहा गया है कि प्रतिवादी-वादी विवाद में संपत्ति के मालिक हैं और अपीलकर्ता-प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा उन्हें वाद के पैरा संख्या 2 में वर्णित नोटिस भेजा गया है। विवाद में बंगले को सरकार के तहत 'पुराने अनुदान' शर्तों के रूप में संदर्भित करके, इसलिए, सरकार ने उक्त भूमि और उस पर मौजूद इमारत को फिर से शुरू करने का फैसला किया और इसलिए, सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसे छोड़ने का नोटिस दिया गया है। दिया जा रहा है और उत्तरदाताओं-वादी को नोटिस की सेवा की तारीख से एक महीने की समाप्ति पर सैन्य संपदा अधिकारी, अंबाला सर्कल, अंबाला कैंट को उस पर खड़ी संरचना के साथ कब्जा देने के लिए कहा गया था। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोटिस तामील होने की तिथि से एक माह की समाप्ति पर उक्त भूमि एवं भवन में प्रतिवादियों-वादीगणों का कब्जा एवं उनसे संबंधित सभी अधिकार, सुख-सुविधाएं एवं हित यथावत रहेंगे। उक्त तिथि से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नोटिस के साथ रुपये का चेक भी था। उक्त भूमि पर अधिकृत निर्माण का मूल्य 64126 है। हालाँकि, उक्त चेक उत्तरदाताओं-वादी द्वारा 18 अप्रैल के अपने पत्र के माध्यम से वापस कर दिया गया था। 1975 में विरोध करते हुए कहा गया कि संपत्ति की बहाली अस्पष्ट और अनिश्चित है और संपत्ति की बहाली के लिए नोटिस में कोई आधार या कारण का उल्लेख नहीं किया गया है और मुआवजे की राशि अत्यधिक अपर्याप्त है और स्वीकार्य नहीं है। उक्त नोटिस को उत्तरदाताओं-वादी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि भारत के नागरिक की कोई भी संपत्ति कानून के अनुसार अर्जित नहीं की जा सकती है और यह नोटिस भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के भी विपरीत है। .छावनी अधिनियम.

1924 और गृह आवास अधिनियम, 1926; नोटिस में किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य या बहाली का उल्लेख नहीं किया गया है; यह नोटिस भी भेदभावपूर्ण है क्योंकि निजी धारकों के बंगले और अन्य व्यक्तियों के समान रूप से स्थित बंगलों को फिर से शुरू नहीं किया गया है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के मद्देनजर नियमों और विनियमों का कोई बेड़ा नहीं रह गया है। यह भारत के संविधान और भारत के कानूनों के साथ असंगत है; कि जीआईआर नंबर 287/डी, अंबाला छावनी, दिनांक 12 सितंबर, 1936 के तहत संपत्ति को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है कि लीज होल्ड अधिकारों के लिए दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है क्योंकि उत्तरदाताओं-वादी ने उसी और वर्तमान बाजार के नवीनीकरण में 1,00,000 रुपये खर्च किए थे। इसका मूल्य रुपये से अधिक है। 3,00,000 कि लीज होल्ड अधिकार का मूल्य लगभग रु. अन्य गेटों, बाड़ों और तारों आदि का मूल्य 50,000 रुपये है। 10,000 और अनुलग्नक का मूल्य रु. 50,000 कि बहाली का नोटिस जारी करने से पहले उत्तरदाताओं-वादी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और इसलिए, नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

(5) यह भी कहा गया है कि विवादग्रस्त भूमि पर खड़ी संरचना के बाजार मूल्य का आकलन करने से पहले प्रतिवादी-वादी को कोई नोटिस और सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है। यह भी दलील दी गई है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी अतिक्रमणकारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। मुकदमा दायर करने से पहले अपीलकर्ता-प्रतिवादी को सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 80 के तहत नोटिस भी दिया गया था। अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने उत्तरदाताओं-वादीगण द्वारा दायर मुकदमे का विरोध किया। इंटर सिलिया, इस आधार पर कि विवाद में भूमि सर्वेक्षण संख्या 356 में से 1.60 एकड़ की रक्षा भूमि है, जिसे बंगला नंबर 102 के रूप में जाना जाता है और इसे जीजीओ द्वारा शासित "ओल्ड ग्रांट" शर्तों के तहत उत्तरदाताओं-वादी द्वारा रखा गया था। क्रमांक 179 दिनांक 12 सितम्बर। 1836. उक्त संपत्ति को फिर से शुरू करने का नोटिस उत्तरदाताओं-वादी को विधिवत दिया गया था और उन्हें उक्त जीजीओ के नियमों और शर्तों के अनुसार 30 दिनों के भीतर इसे सौंपने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, चूंकि उत्तरदाताओं-वादी ने नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद भी विवाद में संपत्ति का कब्जा सौंपने से इनकार कर दिया था, इसलिए, अब वे सार्वजनिक परिसर के अनधिकृत कब्जेदार हैं और इसलिए, अपीलकर्ता-प्रतिवादी-भारत संघ ने कार्यवाही शुरू कर दी है सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का केंद्रीय अधिनियम XI), (संक्षेप में '1971 अधिनियम') के प्रावधानों के तहत संपदा अधिकारी, अंबाला सर्कल, अंबाला कैंट के न्यायालय में, और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि 1971 अधिनियम की धारा 15 के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। विशेष दलील दी गई है कि उत्तरदाताओं-वादी के पास जीजीओ संख्या 179, दिनांक 12 सितंबर, 1836 के तहत "ओल्ड ग्रांट"* अवधि पर अपीलकर्ता-प्रतिवादी-भारत संघ के लाइसेंस के रूप में विवाद में भूमि का कब्जा है और

वह राष्ट्रपति हैं। भारत संपत्ति को फिर से शुरू करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है और यह नोटिस उक्त जीजीओ नंबर 179 के नियमों और शर्तों के अनुसार जारी किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले को भूमि अधिग्रहण मामला नहीं कहा जा सकता है और यह यह भी नहीं कहा जा सकता कि संविधान के लागू होने के बाद पिछले सभी अनुबंध, नियम और विनियम समाप्त हो गये। जीजीओ. क्रमांक 179. जिसके तहत भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, प्रतिवादी-वादी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इमारत को उक्त जीजीओ के नियमों और शर्तों के तहत फिर से शुरू किया गया है। विशिष्ट दलील दी गई है कि उक्त जीजीओ के नियम और शर्तों को उत्तरदाताओं-वादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसलिए अब वे यह दलील नहीं दे सकते कि यह उन पर बाध्यकारी नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि विवादग्रस्त भूमि पर निर्माण के लिए अधिकृत सुपर स्ट्रक्चर के लिए सैन्य इंजीनियरों द्वारा उत्तरदाताओं-वादी को दिए गए मुआवजे का सही मूल्यांकन किया गया है और संपूर्ण रूप से उत्तरदाताओं-वादी को भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न में बंगले की भूमि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की है और इन तथ्यों को उत्तरदाताओं-वादी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था जब भूमि उन्हें जीजीओ के नियमों और शर्तों के तहत दी गई थी। संख्या 179. आगे दलील दी गई है कि सुपर स्ट्रक्चर का मूल्यह्रास मूल्य प्रतिवादी-वादी को देय है और इसलिए, रुपये की राशि। उन्हें 64,126 रुपये की पेशकश की गई थी और हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि चेक उत्तरदाताओं-वादी द्वारा वापस कर दिया गया था। संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार कर लिया गया था, हालांकि, यह दलील दी गई कि यह मान्य नहीं था और इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उत्तरदाताओं-वादीगणों द्वारा दायर लिखित बयान की प्रतिकृति में, इस बात से इनकार किया गया है कि जीजीओ के अनुसार "ओल्ड ग्रांट" शर्तों के तहत विवाद में संपत्ति पर उनका कब्जा है। क्रमांक 179 दिनांक 12 सितम्बर 1836.

(8) पक्षों की दलीलों से, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए-

(9) क्या वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आक्षेपित नोटिस अवैध, असंवैधानिक, क्षेत्राधिकार के बिना, अधिकार क्षेत्र से बाहर है जैसा कि वादपत्र में आरोप लगाया गया है? ऑप

(2) क्या सिविल न्यायालयों के पास मनोरंजन का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

वर्तमान सूट? ओपीडी

(3) राहत।''

(9) पक्षों ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 1 का निर्णय उत्तरदाताओं-वादीगणों के पक्ष में यह कहते हुए दिया कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि उक्त नोटिस जारी करने से पहले उत्तरदाताओं-

वादीगणों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। सुपर स्ट्रक्चर के मूल्य का आकलन करने से पहले उत्तरदाताओं-वादी को दिया जा रहा है और यहां तक कि नोटिस भी भेदभावपूर्ण है क्योंकि आसपास के भवन के मालिकों को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

(10) अंक संख्या 2 का निर्णय भी प्रतिवादी-वादी के पक्ष में और अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विरुद्ध किया गया है।

(11) अंक संख्या 3 का निर्णय उत्तरदाताओं-वादी-प्रतिवादियों के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ भी किया गया है और हालांकि, मुद्दा संख्या 3 का निर्णय करते समय, यह देखा गया कि विवाद में संपत्ति उत्तरदाताओं-वादी द्वारा "पुराने अनुदान" पर रखी जा रही है। शर्तें और वे जी.जी.ओ. की शर्तों से बंधे हैं। क्रमांक 179 दिनांक 12 सितंबर 1936 मुख्यतः इस आधार पर कि उक्त तथ्य को उत्तरदाताओं-वादी द्वारा स्वीकार किया गया है, जैसा कि विक्रय विलेख उदाहरण में स्पष्ट है। डी1,—जिसके तहत विवादग्रस्त संपत्ति उत्तरदाताओं-वादी द्वारा पिछले मालिक से खरीदी गई थी।

(12) विभिन्न मुद्दों पर निष्कर्षों की अगली कड़ी में, उत्तरदाताओं-वादीगणों के मुकदमे का आदेश दिया गया था और उनके पक्ष में इस आशय की घोषणा के लिए एक डिक्री प्रदान की गई थी कि उप निदेशक, सैन्य भूमि और छावनी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नोटिस, एम.एल. एंड सी, डीटीई, नई दिल्ली, विवाद में संपत्ति की बहाली के संबंध में अवैध, शून्य, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और उत्तरदाताओं-वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने विद्वान जिला न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष अपील दायर की, हालांकि, चूंकि अपील सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, इसलिए परिसीमा की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए अधिनियम भी दायर किया गया था।

(14) आवेदन का उत्तरदाताओं-वादीगणों द्वारा विरोध किया गया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपील दायर करने में हुई देरी की माफी के लिए आवेदन पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए और उसका उत्तर दिया:

"क्या देरी माफ़ करने के लिए पर्याप्त आधार हैं?"

(15) पार्टियों ने उक्त मुद्दे पर अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने श्री ए.पी. सिंह, सैन्य संपदा अधिकारी, अंबाला कैंट से एडब्ल्यू1 और श्री आर.के. से पूछताछ की। श्रीवास्तव, सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन, सैन्य संपदा अधिकारी, अंबाला कैंट, AW2 के रूप में। हालाँकि, इस बिंदु पर उत्तरदाताओं-वादी द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए अपीलकर्ता-

प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और इसके परिणामस्वरूप अपील को भी खारिज कर दिया, क्योंकि सीमा और डिक्री की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था- तदनुसार शीट तैयार की गई।

(16) विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय ने 7 दिसंबर, 1983 को सुनवाई के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना स्वीकार कर लिया था। .

(17) घनपत बनाम राम देवी मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने, (1) यह विचार किया था कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के मद्देनजर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधान, (1) एआईआर 1978 पीबी. एवं हाई. 1976 में संशोधित 137, इस न्यायालय में दायर दूसरी अपीलों पर लागू नहीं थे और तदनुसार, कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, न ही कानून के ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उपरोक्त नियमित दूसरी अपीलें स्वीकार की गईं थीं। हालाँकि, कुलवंत कौर बनाम गुरदयाल सिंह मान (मृत) बाय एल. रु. (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वर्ष 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद, धारा 100, धारा 41 में संशोधन किया गया। पंजाब न्यायालय अधिनियम निरर्थक हो गया था और केंद्रीय अधिनियम, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रतिकूल हो गया था और इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना था और इसलिए, दूसरी अपील केवल संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत इस न्यायालय में होगी। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि वर्तमान अपील की स्वीकृति के समय कानून का प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, और फिर भी, दयाल सरूप बनाम ओम प्रकाश (मृतक के बाद से) एल के माध्यम से इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा देखा गया है .आरएस और अन्य, (3) कि यह न्यायालय अपील की सुनवाई से पहले किसी भी समय, यहां तक कि अपील के आधारों में संशोधन किए बिना, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत विचार किए गए कानून का प्रश्न तैयार कर सकता है। यह भी माना गया है कि संहिता की धारा 100(4) और 100(5) के तहत अपील की सुनवाई करते समय कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना न्यायालय का कर्तव्य है और कानून के प्रश्न को किसी भी स्तर पर उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

(19) इसलिए, इस कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील को इस अपील में उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न दायर करने के लिए कहा गया था।

(20) अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न दायर किए हैं, जो इस अपील में उठ रहे हैं-

(21) क्या 7 अप्रैल, 1975 को पुनः आरंभ करने का नोटिस अवैध है क्योंकि यह सुनवाई का अवसर देने और मुआवजा निर्धारित करने की एक शर्त है?

(2) क्या जी.जी.ओ. के दावे 6 के तहत जारी किए गए नोटिस में निष्कर्ष निकाला गया है और संपत्ति को "ओल्ड ग्रांट बेसिस" के तहत रखा गया है। 12 सितंबर 1836 की संख्या 179 को अवैध और मनमाना मानकर रद्द किया जा सकता है?

(3) क्या निम्न विद्वान न्यायालयों द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्णय और डिक्री कानून के विरुद्ध है?

(4) क्या अपील समय बाधित होने के कारण खारिज की जा सकती है

अन्य मुद्दों और कानून बिंदुओं पर निर्णय किए बिना?

(21) मैंने इस अपील में उठने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है, और पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है। मामला (सुप्रा) और निम्नानुसार देखा गया-

(23) लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या 1949 बीओएम 400 और 1952 बीओएम 157 में अपनाया गया दृष्टिकोण, कि एक अपील जो सीमा की अवधि से परे दायर की जाती है, कानून की नजर में, कोई अपील नहीं है, जब तक कि कोई माफी न हो देरी का, और परिणामस्वरूप, उस पर पारित आदेश को अपील में पारित नहीं माना जा सकता है, ताकि वह धारा 31 के अंतर्गत आए, सही है। अब, अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है, और क़ानून का एक अंग है। धारा 30 (1) निर्धारिती को कुछ आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करती है, और धारा 23 के तहत मूल्यांकन का आदेश उनमें से एक है। इसलिए अपीलकर्ता के पास आयकर अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ अपील करने का धारा 30 (1) के तहत वास्तविक अधिकार था। फिर, हम धारा 30(2) पर आते हैं, जो एक सीमा अवधि लागू करती है जिसके भीतर इस अधिकार का प्रयोग किया जाना है। यदि कोई अपील उस समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो क्या धारा 20(1) के तहत प्रावधान के अनुसार वह अपील नहीं रह जाएगी?

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सीमा के नियम, विशेषण कानून के क्षेत्र से संबंधित हैं, और वे केवल उपाय को रोकने के लिए काम करते हैं, लेकिन अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं। इसलिए, धारा 30(1) के अनुसार की गई अपील, कानून की नजर में एक अपील होनी चाहिए, हालांकि धारा 30(2) में उल्लिखित अवधि से परे प्रस्तुत किए जाने पर इसे खारिज किया जा सकता है। क़ानून में ऐसा प्रावधान हो सकता है कि निर्धारित सीमा अवधि के अंत में, अधिकार समाप्त हो जाएगा, उदाहरण के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 28; लेकिन यहां ऐसा कोई नहीं है।

दूसरी ओर, धारा 30 (1) के तहत अपील का अधिकार प्रदान करने और धारा 30 (2) के तहत अलग से इसके अभ्यास के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने में, विधायिका ने इसके तहत अच्छी तरह से

मान्यता प्राप्त भेद को बनाए रखने का इरादा दिखाया है। वास्तविक अधिकार क्या है और प्रक्रियात्मक कानून का मामला क्या है, के बीच सामान्य कानून। नागेंद्रनाथ बनाम सुरेश चंद्र डे (3) में सर दिनशॉ मुल्ला ने लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 182 के तीसरे कॉलम में 'अपील' शब्द का अर्थ लगाते हुए कहा:
"सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उनके आधिपत्य में इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पक्ष द्वारा अपीलीय न्यायालय में किया गया कोई भी आवेदन, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के लिए कहा गया हो, एक अपील है। शब्द की सामान्य स्वीकृति, और यह किसी अपील से कम नहीं है क्योंकि यह अनियमित या अक्षम है"।
इन टिप्पणियों को राजा कुलकर्णी और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1954 एससी 73 में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था और अपनाया गया था। प्रोमोथो नाथ रॉय बनाम डब्ल्यू.ए. ली, एआईआर 1921 कैल 415 में, एक आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज करने का आदेश दिया गया था। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन को खारिज करने के बाद प्रस्तुति में देरी को माफ करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अर्थ के भीतर "अपील पर पारित" माना गया था। इन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर, यह माना जाना चाहिए कि समय से बाहर प्रस्तुत की गई अपील एक अपील है, और इसे समय-बाधित के रूप में खारिज करने वाला आदेश अपील में पारित किया गया आदेश है।
श्योदान सिंह बनाम दरियाओ कुँवर (13) में सर्वोच्च न्यायालय के चार माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए बाद के फैसले में, यह सवाल फिर से उठता है कि क्या किसी डिक्री से अपील को इस आधार पर खारिज करना कि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित थी, अपील में एक निर्णय था, इसे इस प्रकार देखा गया-
“14 इसलिए हम इस बात पर एकमत हैं कि क्या कोई निर्णय दिया गया है।
ट्रायल कोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर और मामले को अपील में ले जाया जाता है और अपील को कुछ प्रारंभिक आधारों पर खारिज कर दिया जाता है, जैसे मुद्रण में सीमा या डिफ़ॉल्ट, यह माना जाना चाहिए कि ऐसी बर्खास्तगी तब होती है जब यह गुण-दोष के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करता है यह अपने आप में अपील की सुनवाई और अंततः अपील को खारिज करने का आधार जो भी हो, गुण-दोष के आधार पर तय किया जाना है।''
(26) श्याम सुंदर सरमा के मामले (सुप्रा), शियो डैन के मामले (सुप्रा) और मेसर्स मेला राम एंड संस के मामले पर भरोसा करते हुए श्याम सुंदर सरमा के मामले (सुप्रा) में माननीय शीर्ष न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में केस (सुप्रा) और रतन सिंह बनाम विजय सिंह और अन्य पर विचार करते समय, (14) यह निम्नानुसार देखा गया-

विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए रतन सिंह बनाम विजय सिंह और अन्य (2001) एससीसी 469 के फैसले पर भरोसा जताया और बताया कि इसमें यह माना गया था कि देरी की माफी के लिए एक आवेदन को खारिज करना कोई अपराध नहीं होगा। डिक्री और, इसलिए, कालबाधित के रूप में अपील को खारिज करना भी डिक्री नहीं था। वह निर्णय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में दिया गया था। 1963 और परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 182 के तहत प्राप्त पिछली स्थिति से विचलन के आलोक में, लेकिन हमें सम्मान के साथ यह बताना चाहिए कि मेसर्स मेला राम एंड संस और श्योदान सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय थे उनके आधिपत्य के ध्यान में नहीं लाया गया। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मैसर्स मेला राम एंड संस (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत और श्योदान सिंह (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया गया और दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न पर सही कानून निर्धारित करने के रूप में स्वीकार किया गया। निःसंदेह, उनके आधिपत्य ने कहा है कि वे जानते थे कि उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों ने यह विचार किया है कि किसी अपील को इस आधार पर खारिज करना कि इसे समय से पहले प्रस्तुत किया गया था, संहिता में प्राप्त डिक्री की परिभाषा के भीतर एक डिक्री है। इसके बाद ऊपर उल्लिखित कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निष्कर्ष में उनके आधिपत्य स्पष्ट रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। यद्यपि नागेंद्र नाथ डे बनाम सुरेश चंद्र डे (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसे इस आधार पर लागू नहीं किया गया था कि यह परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 182 पर आधारित था, और इसमें एक विचलन था। परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 136 के मद्देनजर कानूनी स्थिति। लेकिन सम्मान के साथ, हमें यह बताना चाहिए कि निर्णय वास्तव में मेसर्स मेला राम एंड संस और श्योदान सिंह (सुप्रा) और इसके एक अन्य निर्णय के निर्णय के अनुपात के साथ संघर्ष करता है। रानी चौधरी बनाम लेफ्टिनेंट कोट सूरज जीत चौधरी [(1982) 2 एससीसी 596)] में दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत अदालत। एस्सार कंस्ट्रक्शन बनाम एन. पी. राम कृष्ण रेड्डी, 2000(3) आरसीआर (सिविल) 281, [(2000) 6 एससीसी 94) में इस न्यायालय के दो अन्य विद्वान न्यायाधीशों ने हमारे ध्यान में लाया, जिन्होंने प्रश्न खुला छोड़ दिया। इसलिए, उस निर्णय पर निर्भरता से अपीलकर्ता को कोई फायदा नहीं होगा।''

(27) इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, भले ही किसी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि इसे समय से पहले प्रस्तुत किया गया था, वही डिक्री प्राप्त करने की परिभाषा के भीतर एक डिक्री है।

(28) अतः प्रतिवादी-वादीगण के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वर्तमान नियमित द्वितीय अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपील दायर करने में केवल 67 दिनों की देरी हुई थी और अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा आवेदन में और पहले दिए गए हलफनामे में पर्याप्त कारण दिए गए हैं। अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय और यहां तक कि इस बिंदु पर अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य भी अप्रमाणित रहे क्योंकि उत्तरदाताओं-वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और, हालांकि, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे अस्वीकार करने में अवैधता की गई है। अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अपीलकर्ता-प्रतिवादी का अनुरोध और, सबसे पहले, वर्तमान नियमित दूसरी अपील की स्थिरता के बारे में उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा एक आपत्ति ली गई है, ओह आधार यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अपील का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है और इसे केवल सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया है और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी के लिए उचित कदम संहिता की धारा 115 के तहत एक पुनरीक्षण दायर करना था, न कि नियमित दूसरा। निवेदन। इस बिंदु पर उन्होंने आयुक्त, हुबली-धनवाद नगर निगम बनाम श्रीशैल और अन्य, जोगेंद्र प्रसाद सिंह और अन्य बनाम सत्य नारायण सिंह और अन्य, रामभरोसे सिंह बनाम हेमलता आठले में दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया है। दया राम बनाम डिविजनल इंजी. (ओ एण्ड एम), म.प्र. चुनाव. बोर्ड, बूटा राम बनाम हरनाम सिंह, 11 अगस्त, 2009 को सीआर नंबर 221 ऑफ 2005 में फैसला सुनाया गया, एस. सतनाम सिंह और अन्य बनाम सुरेंद्र कौर और अन्य और ख. अली मोहम्मद. बनाम सरकार के मुख्य सचिव, और अन्य।

(25) दूसरी ओर, अपीलकर्ता-प्रतिवादी-भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, हो सकता है कि यह सीमा के आधार पर हो, यही अपील में निर्णय के समान है और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में विलय हो गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में डिक्री भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तैयार की गई थी और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ केवल नियमित दूसरी अपील ही सुनवाई योग्य है। इस अपील में उत्पन्न हो रहा है. उन्होंने श्याम सुंदर सरमा बनाम पन्नालाल जयसवाल और अन्य पर भी भरोसा जताया है।

यह प्रश्न कि क्या कोई अपील, जिसके साथ अपील दायर करने में हुई देरी की माफ़ी के लिए आवेदन भी जुड़ा हो, कानून की नज़र में अपील है, जब अपील दायर करने में हुई देरी की माफ़ी का आवेदन खारिज कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप अपील भी खारिज कर दी जाती है। लिमिटेशन अधिनियम की धारा 3 के मद्देनजर, लिमिटेशन द्वारा वर्जित होने पर प्रिवी काउंसिल द्वारा नागेंद्रनाथ बनाम सुरेश चंद्र, में विचार किया गया और इसे इस प्रकार देखा गया-

"सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उनके आधिपत्य में इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पक्ष द्वारा अपीलीय न्यायालय में किया गया कोई भी आवेदन, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के लिए कहा गया हो, एक अपील है। शर्तों की सामान्य स्वीकृति, और यह किसी अपील से कम नहीं है क्योंकि यह अनियमित या अक्षम है।

(29) मेसर्स मेला राम एंड संस बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस विशिष्ट प्रश्न पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि परिसीमा के बाद प्रस्तुत की गई अपील यह एक अपील है और नागेंद्रनाथ के प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा करते हुए इसे समयबाधित मानकर खारिज करने का आदेश अपील पर आधारित है, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर देना चाहिए था और फैसला करना चाहिए था। इस मामले में शामिल कानून बिंदु को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष के आधार पर समान। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि कानून संख्या 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में और उत्तरदाताओं-वादी के खिलाफ तय किया जाना आवश्यक है।

(30) दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपील दायर करने में देरी को माफ करने का कोई आधार अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा नहीं बनाया गया था और इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही ही खारिज कर दिया है। देरी की माफ़ी के लिए आवेदन किया गया और अपील को उचित रूप से खारिज कर दिया गया क्योंकि निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया है। अपील दायर करने में देरी को माफ करने के बिंदु पर कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में ओरिएंटल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम और अन्य में दिए गए फैसले में तय किया गया है, जिसमें परिवर्तन किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले सभी निर्णयों में, यह देखा गया कि देरी की माफ़ी के लिए आवेदनों से निपटने में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं बनाया जा सकता है और छोटी अवधि की देरी को माफ़ करने में एक उदार दृष्टिकोण और सख्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। जहां देरी अत्यधिक हो, उसे अपनाया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया कि हालांकि देरी की माफी के लिए, निजी व्यक्तियों और राज्य द्वारा दायर

देरी की माफी के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक ही मानदंड लागू किया जाना चाहिए और, हालांकि, बाद के मामले में कुछ अक्षांश की अनुमति नहीं है क्योंकि राज्य प्रतिनिधित्व करता है समुदाय के सामूहिक उद्देश्य और निर्णय अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा धीमी गति से लिए जाते हैं और फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजने की बोझिल प्रक्रिया में काफी समय लगता है, जिससे देरी होती है, उसी का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है: -

हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। परिसीमा का नियम सार्वजनिक नीति पर आधारित है। विधायिका पार्टियों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य से सीमा निर्धारित नहीं करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वे टाल-मटोल की रणनीति का सहारा न लें और बिना देरी के उपाय खोजें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायिका द्वारा निर्धारित अवधि तक जीवित रखा जाना चाहिए। इसे अलग ढंग से कहें तो, परिसीमा का कानून एक अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी चोट के निवारण के लिए कानूनी उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, यदि निर्धारित समय के भीतर उपचार का लाभ नहीं उठाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो अदालतों को देरी को माफ करने की शक्ति दी जाती है। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और इसी तरह के अन्य क़ानूनों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" इतनी लोचदार है कि अदालतें कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम हो सकती हैं जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करता है। हालाँकि, देरी की माफी के लिए आवेदनों से निपटने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय ने छोटी अवधि की देरी को माफ करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने और जहां देरी अत्यधिक है, वहां सख्त दृष्टिकोण अपनाने की उचित वकालत की है- कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम एमएसटी। कातिजी (1987) 2 एससीसी 107, एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति, 1992 (2) आरसीआर (सिविल) 578, (1998) 7 एससीसी 123 और वेदाबाई बनाम शांताराम बाबूराव पाटिल, 2001 (3) आरसीआर (सिविल) 831 : (2001) 9 एससीसी 106। राज्य और उसकी एजेंसियों/उपकरणों की ओर से दायर देरी की माफी के लिए आवेदनों से निपटने में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि निजी व्यक्तियों द्वारा दायर देरी की माफी के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समान मानदंड लागू किया जाना चाहिए। और राज्य ने देखा कि बाद के मामले में कुछ अक्षांश की अनुमति नहीं है क्योंकि राज्य समुदाय के सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करता है और निर्णय अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा धीमी गति से लिए जाते हैं और फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक धकेलने की जटिल प्रक्रिया होती है। तालिका में काफी समय लगता है जिससे देरी होती है - जी रामेगौड़ा बनाम विशेष। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, 1988(1) आरआरआर 555, (1988) 2 एससीसी 142, हरियाणा राज्य बनाम चंद्र मणि, 1996(2) आरआरआर 82: (1996) 3 एससीसी 132, उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम हरीश चंद्र, 1996(2) एससीटी 712: (1996) 9 एससीसी

309, बिहार राज्य बनाम रतन लाल साहू, (1996) 10 एससीसी 635, नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ, 2005(2) आरसीआर (सीआरएल.)414 :2005 (2) आरसीआर (सिविल)375:2005(2) एपेक्स क्रिमिनल 75: (2005) 3 एससीसी 752, और राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम अहमद जान 2008(4) आरसीआर (क्रिमिनल) 119: 2008(4) आरसीआर (सिविल) 126: 2008 (4) एससीटी 25: 2008(2) आरसीआर (किराया) 234: 2008(5) राज 214: (2008) 14 एससीसी 582।"

इसलिए, इस कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील दायर करने में 67 दिनों की देरी को माफ करने के लिए अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार करने में अवैधता की है।

(33) प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-प्रतिवादी की ओर से दायर आवेदन और शपथ पत्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि देरी की माफी के लिए निम्नलिखित आधार लिए गए थे-

"(i) निचली अदालत के फैसले को कानूनी सलाहकार (रक्षा) को संदर्भित किया गया था जो 19 जून, 1980 को महानिदेशक, रक्षा भूमि और छावनी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। स्थिति से अवगत कराने के लिए इसे 21 जून, 1980 को फिर से रक्षा मंत्रालय को भेजा गया। उनके द्वारा मामले की जांच की गई और उन्हें लगा कि निचली अदालत के फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि फैसले में बुनियादी मुद्दे उठाए गए हैं।

(ii) मामला कुछ मुद्दों पर पुनः जांच के लिए 22 जुलाई, 1980 को महानिदेशालय, डीएल एंड सी नई दिल्ली को वापस प्राप्त हुआ था।

(iii) मामला 16 अगस्त, 1980 को पूरे डेटा के साथ फिर से रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। रक्षा मंत्रालय ने महसूस किया कि विचाराधीन फैसले ने मौलिक बिंदु उठाए हैं और इन दोनों बिंदुओं पर न्यायालय के फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अंबाला के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई तो बड़ी संख्या में मामलों और व्यापक जनहित पर बहुत प्रतिकूल और भौतिक प्रभाव पड़ेगा।

(iv) उपरोक्त के मद्देनजर मामला 18 अगस्त, 1980 को एक बार फिर कानूनी सलाहकार (रक्षा) के पास भेजा गया। तब कानूनी सलाहकार (रक्षा) ने देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ अपील दायर करने की सलाह दी।

(v) कानूनी सलाहकार (रक्षा) के निर्णय से मुझे महानिदेशक, रक्षा भूमि एवं छावनी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 21 अगस्त, 1980 को अवगत कराया गया। 22 अगस्त, 1980 से 29 अगस्त, 1980 तक की अवधि को इसमें लिया गया है। जिला अटॉर्नी, अंबाला के साथ परामर्श करना और अपील तैयार करना।"

अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा इस बिंदु पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया, जिसका खंडन नहीं किया गया। इसलिए, मेरे विचार में अपील दायर करने में देरी को अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया गया है, क्योंकि फ़ाइल को रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर निपटाया गया था, और यह कानूनी सलाहकार की राय प्राप्त करने के बाद ही किया गया था। (रक्षा), 21 अगस्त, 1980 को महानिदेशक, रक्षा भूमि और छावनी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपील दायर करने के निर्णय के बारे में सैन्य संपदा अधिकारी, अंबाला सर्कल, अंबाला कैंट को सूचित किया गया था और इसमें केवल कुछ ही दिन लगे थे। अपील की तैयारी, जो 30 अगस्त, 1980 को दायर की गई थी। इसलिए, प्रथम अपीलकर्ता न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने में अवैधता की है।

(35) उक्त आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है और अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाता है और इसलिए, उपरोक्त कानून संख्या 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ तय किया जाता है- वादी.

(36) हालाँकि, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान नियमित दूसरी अपील वर्ष 1983 से स्वीकार की गई है और इसलिए, वह इस मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेजने के लिए दबाव नहीं डालती है। इस मामले में शामिल बिंदुओं पर योग्यता। बल्कि, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष को उलटने के लिए दबाव नहीं डालते हैं और, हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान अपील का निर्णय केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उत्तरदाताओं-वादी के मुकदमे को डिक्री करने में अवैधता की है, यह मानने के बाद कि उत्तरदाताओं-वादी विवाद में संपत्ति के कब्जे में हैं, "ओल्ड ग्रांट" शर्तों के रूप में, और यह मानने के बाद कि वे जीजीओ के नियमों और शर्तों से बंधे हैं। क्रमांक 179.

(37) इसलिए, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति के मद्देनजर, मैंने इस अपील में उत्पन्न होने वाले कानून संख्या 1 से 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पार्टियों के विद्वान वकील को भी सुना है, और पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर योग्यता के आधार पर इस अपील की सुनवाई के बाद, जैसा कि ऊपर बनाया गया है, और इस न्यायालय द्वारा इसे आदेश के लिए आरक्षित किए जाने के बाद और हालांकि आदेश सुनाए जाने से पहले, एक आवेदन के तहत उत्तरदाताओं-वादी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति के लिए संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41

नियम 27 दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी मुद्दों का निर्णय उत्तरदाताओं-वादी के पक्ष में किया गया था और उनके मुकदमे का फैसला भी किया गया था और, हालांकि, मुद्दा संख्या 3 पर निर्णय लेते समय, यह देखा गया कि उत्तरदाताओं-वादी ने अपनी जगह पर कदम रखा है उनके पूर्ववर्ती-हित के और उन्हीं नियमों और शर्तों से बंधे हैं जिनके तहत उनके हित-पूर्ववर्ती द्वारा उचित रूप से धारण किया गया था और इसलिए, उत्तरदाताओं-वादीगण वाद संख्या 3 पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के उक्त निष्कर्ष को चुनौती देने का इरादा रखते हैं। .

(39) अपीलार्थी-प्रतिवादी द्वारा उत्तर दाखिल कर आवेदन का विरोध किया गया है।

(40) मैंने उक्त आवेदन पर पक्षों के विद्वान वकीलों को भी सुना है।

उत्तरदाताओं-वादीगणों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं-वादीगण क्रॉस-अपील/आपत्तियां दायर करके और फिर भी आदेश 41 नियम 22 के तहत मुद्दा संख्या 3 के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को चुनौती दे सकते थे। कोड, प्रतिवादी-वादी दूसरे पक्ष द्वारा दायर अपील की सुनवाई के समय नीचे के न्यायालयों के निष्कर्ष पर हमला कर सकते हैं। यह तर्क दिया गया है कि इस तथ्य को साबित करने के लिए कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी दोनों ही बंगला नंबर के नीचे की भूमि के मालिक नहीं थे। 102, माल रोड, अम्बाला कैंट। विवाद में 1.82 एकड़ की माप, न ही अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया था कि विवाद में बंगले के नीचे की भूमि उनके पास निहित है, उत्तरदाताओं-वादी अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहते हैं। यह तर्क दिया गया है कि मामले के उचित निर्णय के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य बहुत आवश्यक है और यह कई मामलों में माना गया है, जहां अतिरिक्त साक्ष्य न्यायालय को अधिक प्रभावी ढंग से और न्यायिक रूप से निर्णय सुनाने में मदद करते हैं, उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य अनुमत। इस बिंदु पर, एस. नजीर अहमद बनाम स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और अन्य, गुरदयाल सिंह और अन्य बनाम माम चंद और अन्य, चंदगी बनाम मेहर चंद और अन्य जैसे कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है। मेहर चंद बनाम लछमी, ए.पी. राज्य वक्फ बोर्ड, हैदराबाद बनाम ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस (शाखा ए.पी.) और अन्य, रविंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह और अन्य, मै. अम्बा माँ मिल्स बनाम हरियाणा राज्य भारत। देव. कॉर्प, और दूसरा गुरदयाल सिंह बनाम रशपाल कौर, दिलबाग सिंह बनाम अमर सिंह वी.के. छाबड़ा बनाम समीर भाटिया और अन्य, बसाखा सिंह बनाम जीत सिंह, परगट सिंह बनाम जीत सिंह, उत्तर पूर्व रेलवे प्रशासन, गोरखपुर बनाम भगवान दास, (डी) एलआर द्वारा। पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम श्री नीको, गुरदयाल सिंह बनाम गुलशन कुमार, श्याम गोपाल बिंदल एवं अन्य बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अन्य, जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम श्रीमती। कैलाशवती देवी, बिल्ला जगन मोहन रेड्डी और अन्य बनाम बिल्ला संजीव रेड्डी और अन्य, गुरनेक सिंह बनाम गुरबचन सिंह, दुर्गा भगवती इंडस्ट्रीज, हाथरस और अन्य बनाम

ओम प्रकाश लोहिया और अन्य, एम/ s गणपति उद्योग, ग्राम एवं पी.ओ. कुलाना और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य, मैसर्स बावा कॉटन जिनिंग आइस एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला , गुरमेक सिंह बनाम गुरबचन सिंह और अश्वनी कुमार बनाम गोपाल कृष्ण।

दूसरी ओर, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान अपील का निर्णय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर किया जा रहा है, क्योंकि यह एक नियमित दूसरी अपील है, न कि तथ्यों पर। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं-वादी द्वारा कोई क्रॉस-अपील/क्रॉस-आपत्ति दायर नहीं की गई थी, बल्कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी की अपील को सीमा के आधार पर उत्तरदाताओं-वादी द्वारा चुनौती दी गई थी और उत्तरदाताओं की याचिका को स्वीकार करके - वादी, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देरी की माफी के लिए अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अनुरोध को अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया और योग्यता के आधार पर अपील पर सुनवाई नहीं की। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान नियमित दूसरी अपील वर्ष 1983 से स्वीकार की जा रही है और अब, जब मामले की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर की गई और आदेशों के लिए आरक्षित कर दी गई, यानी, अपील स्वीकार किए जाने के लगभग 27 साल बाद, वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने का कोई आधार नहीं बनाया गया है कि इस स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। उसने यह भी तर्क दिया है कि आवेदन केवल अतिरिक्त दस्तावेजों और अनुलग्नकों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए है और इसलिए, यह रखरखाव योग्य नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इसके अलावा, जो विवाद अब इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील द्वारा उठाया जा रहा है और जिसके लिए अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की मांग की गई है, उसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय चित्रा कुमार (श्रीमती) द्वारा पहले ही किया जा चुका है। .) बनाम भारत संघ और अन्य, टेक चंद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का फैसला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम सुरेंद्र कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य मामला। वकील और अन्य। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने विक्रय विलेख, पूर्व में कथन पर भरोसा करने के बाद इस बिंदु पर सही ढंग से निर्णय लिया है। डी1, वर्तमान उत्तरदाताओं-वादी द्वारा मूल मालिक से "पुरानी अनुदान" शर्तों पर खरीदारी दिखा रहा है। उत्तरदाताओं-वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है-

“(1) छावनी मैनुअल, 1909 की प्रति;

(2) सैन्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 278 दिनांक 19 दिसम्बर 1873 की प्रति;

(3) अधिसूचना क्रमांक 1488 दिनांक 10 अगस्त 1887 की प्रति;

(4) अम्बाला छावनी में मकानों की संख्यात्मक सूची, मालिकों के नाम और पंजीकृत किराए की प्रति।

(5) अम्बाला छावनी की साइट योजना की प्रति;

(6) विक्रय पत्र क्रमांक 712 दिनांक 18 दिसम्बर 1892 की प्रति;

(7) अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा बनाए गए सामान्य भूमि रजिस्टर से उद्धरण की प्रतिलिपि जिसमें विवाद में संपत्ति से संबंधित प्रासंगिक प्रविष्टियां शामिल हैं;

(8) विक्रय पत्र की प्रति, दिनांक 28 जनवरी 1938;

(9) याचिका विलेख की प्रति, दिनांक 30 मार्च, 1944;

रक्षा संपदा कार्यालय, अंबाला सर्कल, अंबाला कैंट के पत्र की प्रति, दिनांक 3 नवंबर, 2008;

(11) रक्षा संपदा कार्यालय, अंबाला सर्कल, अंबाला कैंट के पत्र की प्रति, दिनांक 28 नवंबर, 2008;

(12) सैन्य संपदा कार्यालय, अंबाला सर्कल, अंबाला छावनी के पत्र की प्रति, दिनांक 6 अक्टूबर, 1941;

(13) छावनी कानून, 2006 के उद्धरण की प्रति, जिसमें बंगले को फिर से शुरू करने के संबंध में कुछ निर्देश शामिल हैं;

(14) कुछ अन्य मामलों में बहाली नोटिस की कार्यवाही की प्रति;

(15) बहाली नोटिस के संबंध में छावनी कानून, 2006 से एक और उद्धरण;

(16) गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 1971 की प्रति;

(17) गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 1973 की प्रति;

(18) कुछ अन्य अधिसूचनाओं की प्रति;

(19) छावनी कानूनों से एक और उद्धरण;

(20) कुछ अन्य बहाली नोटिस की प्रतियां;

(21) विंग कमांडर नगीना सिंह और श्रीमती के मामले में तत्कालीन वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा 1975 के सिविल सूट नंबर 72 में पारित फैसले की प्रति। स्वर्ण कौर बनाम भारत संघ;

(22) 1974 के सिविल सूट नंबर 87 में विजय कुमार शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ मामले में तत्कालीन वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित फैसले की प्रति, जिसका फैसला 19 जनवरी, 1979 को हुआ था;

(23) पंजाब वक्फ बोर्ड, अम्बाला कैंट को जारी नोटिस की प्रति, दिनांक 22 जनवरी, 1971;

(24) पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम भारत संघ मामले में तत्कालीन वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित 29 अप्रैल, 1978 के फैसले की प्रति;

(25) इस न्यायालय द्वारा महेश चंदर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, सी.डब्ल्यू.पी.नं. में पारित एक अन्य निर्णय की प्रति। 1971 का 871, दिनांक 2 मार्च 1971;

विंग कमांडर सांवल शाह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में तत्कालीन उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, अंबाला द्वारा 26 अगस्त, 1976 को पारित आदेश की प्रति।

(27) विजय कुमार शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सिविल सूट नंबर 87/1974 में तत्कालीन वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित निर्णय की प्रति, दिनांक 19 जनवरी, 1979;

(28) सचिव, पंजाब वक्फ बोर्ड, अम्बाला कैंट को जारी नोटिस दिनांक 11 मार्च, 1970 की प्रति;

(29) पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम भारत संघ के मामले में तत्कालीन वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अंबाला द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1978 को पारित निर्णय की प्रति;

(30) छावनी बोर्ड के प्रबंधन के संबंध में छावनी कानूनों के एक अन्य उद्धरण की प्रति;

(31) शिमला में जिला न्यायाधीश अंबाला द्वारा पारित एक अन्य निर्णय की प्रति, दिनांक 24 जुलाई, 1919;

(32) 7 मई 1838 के जीजीओ नंबर 260 के संबंध में सामान्य भूमि रजिस्टर-छावनी 8-ए(एल) से उद्धरण;

(33) लोकसभा सचिवालय से प्राप्त कुछ जानकारी की प्रति, जिसमें सदन आवास विधेयक शामिल है;

(34) पंजाब सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 नवंबर, 1994 की प्रति - जिसके तहत छावनी हाउस आवास अधिनियम 1902 लागू किया गया था;

(35) छावनी आवास आवास) अधिनियम, 1902 और 1923 के तहत अधिसूचित छावनियों की सूची की प्रति;

(36) छावनी (गृह आवास) अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में 19 अप्रैल, 1927 की अधिसूचना की प्रति;

(37) तेजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में एक गवाह के बयान की प्रति;

(38) कुछ अन्य अधिसूचनाओं की प्रति;

(39) कुछ शैक्षणिक संस्थानों के लिए भवन अनुदान के संबंध में वित्तीय विभाग की प्रति;

(40) आयकर रिपोर्ट के मूल्यांकन की प्रति;

(41) कुछ अन्य अधिसूचनाओं की प्रति;

(42) पंजाब गजट की प्रति, दिनांक 27 जनवरी, 1911;

(43) ब्रिटिश संसदीय पत्रों की प्रति;

(44) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861, 1892 और 1909 की प्रति'

(45) भारत के शाही गजेटियर की प्रति;

(46) कैंटोनमेंट हाउस आवास अधिनियम, 1923 की प्रति;

(47) शाही राजपत्र वर्ष 1909 की प्रति;

(48) सैन्य भूमि नियमावली/छावनी भूमि मुआवजा नियमावली की प्रति;

(49) छावनी मैनुअल की प्रति, किसी पुस्तक के पन्ने;

(50) अम्बाला गजेटियर की प्रति, किसी पुस्तक के पन्ने;

(51) अम्बाला उपविधि की प्रति, किसी पुस्तक के पन्ने;

(52) अम्बाला छावनी के अधिकारों की प्रति, 1909, किसी पुस्तक के पन्ने;

(53) छावनी अधिनियम, 1864;

कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आदेश 41 नियम 27 और संहिता की धारा 107 के तहत, उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है, भले ही दस्तावेज़ भीतर हों। अपीलकर्ता का ज्ञान और दस्तावेजी साक्ष्य, जो मुकदमे के फैसले के बाद पहली बार बनाया या निर्मित नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी आधिकारिक दस्तावेज, जिसकी प्रामाणिकता विवाद में नहीं है और अदालत में अंतिम निर्णय लेने के लिए पहुंचने में सक्षम है पक्षों के बीच विवाद के मामले में, ऐसे साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी जा सकती है।

(45) इसलिए, जहां तक उस बिंदु पर कानूनी प्रस्ताव का सवाल है, जैसा कि उपरोक्त अधिकारियों में रखा गया है, जिस पर उत्तरदाताओं-वादी की ओर से भरोसा किया गया है, कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, वर्तमान नियमित दूसरी अपील का निर्णय इस न्यायालय द्वारा कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर किया जा रहा है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-वादी द्वारा कोई प्रति-अपील/प्रति-आपत्ति दायर नहीं की गई। बल्कि वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर अपील का प्रतिवादी-वादी ने परिसीमा के आधार पर विरोध किया था और उसे परिसीमा के आधार पर ही खारिज कर दिया गया था। अधिकांश दस्तावेज़, जिन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की मांग की गई है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ अधिसूचनाओं, अधिनियमों और कुछ अन्य संपत्तियों के संबंध में कुछ निर्णयों और कुछ नोटिसों की प्रतियां हैं, जो छावनी संपत्तियों के कुछ अन्य कब्जेदारों को जारी किए गए हैं। प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील, बहस के समय, इस न्यायालय को यह समझाने में विफल रहे कि वर्तमान अपील और वर्तमान विवाद पर निर्णय लेने के लिए उक्त दस्तावेज़ कैसे आवश्यक हैं।

(46) इसी तरह के तथ्यों पर, चित्रा कुमारी के मामले में (सुप्रा) जिसमें अंबाला छावनी में स्थित एक बंगले को "ओल्ड ग्रांट" शर्तों पर फिर से शुरू करने के लिए भारत संघ द्वारा जारी नोटिस को भी चुनौती दी गई थी, कई दस्तावेजों की मांग की गई थी नियमित द्वितीय अपील के चरण में अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे निम्नानुसार देखा गया

(47) अप्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न कर प्रयास करने की प्रथा अपील में या उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिकाओं में पहली बार उन पर भरोसा करने की निंदा की जानी चाहिए।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे इस प्रकार भी देखा गया-

अपीलकर्ता कभी भी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में नहीं गए। यहां तक कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी यह नहीं कहा गया है कि उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया और/या कानून की उचित प्रक्रिया के बाद फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले फैसले के हिस्से को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय यह भी स्पष्ट कर रहा है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद फिर से काम शुरू कर सकती है। इससे पता चलता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि सरकार भूमि की मालिक थी और भूमि पुराने अनुदान की शर्तों पर थी।

(47) वर्तमान मामले में भी, विवाद संख्या 3 का निर्णय करते समय, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विक्रय-पत्र में किए गए कथन के आधार पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिसके आधार पर प्रतिवादी-वादी इसमें अधिकार का दावा कर रहे हैं। विवाद में संपत्ति, जैसा कि निर्णय के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी और इसलिए, मेरे विचार में, उपरोक्त कोई भी दस्तावेज, जिसे अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की मांग की गई है, पार्टियों के बीच वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है। . इसलिए, संहिता की धारा 151 के साथ पढ़े गए आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने के लिए उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

(48) अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया है कि हालांकि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या 3 पर निर्णय लेते समय माना है कि उत्तरदाताओं-वादी सरकार के तहत "पुराने अनुदान" शर्तों के रूप में विवाद में संपत्ति के कब्जे में हैं। और, हालाँकि, नोटिस को केवल इस आधार पर अवैध ठहराया गया है कि उक्त नोटिस जारी करने से पहले उत्तरदाताओं-वादीगणों को सुनवाई का कोई अवसर जारी नहीं किया गया था और मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने से पहले उत्तरदाताओं-वादीगणों को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। और इसलिए, यह प्राकृतिक न्याय के नियम के विरुद्ध है। हालाँकि, यह तर्क दिया गया है कि टेक चंद के मामले में उक्त बिंदु इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है, और सुरेंद्र कुमार वकील और अन्य (सुप्रा) और चित्रा कुमारी (सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी-वादी साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आए हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि विवादित संपत्ति पर उनका कब्ज़ा कैसे हुआ। आगे यह तर्क दिया गया है कि हालांकि, बिक्री विलेख, - जिसके माध्यम से प्रतिवादी-वादी भारत संघ की भूमि पर खड़े सुपर स्ट्रक्चर के मालिक बन गए, को अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा पूर्व के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। डीआई और उक्त विलेख के पाठ के अनुसार, यह दोनों पक्षों, यानी विक्रेता और विक्रेता, यानी, वर्तमान उत्तरदाताओं-वादी, द्वारा

स्वीकार किया गया है कि जिस भूमि पर इमारत खड़ी थी, वह भारत संघ के स्वामित्व में थी और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि केवल इमारत को पिछले मालिक द्वारा उत्तरदाताओं-वादी के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता-वादी अब यह दलील नहीं दे सकते हैं कि भारत संघ उस भूमि का मालिक नहीं है जिस पर विवाद में इमारत खड़ी है। यह भी तर्क दिया गया है कि कानून भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि बहाली नोटिस को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि उत्तरदाताओं-वादी को नोटिस देने के बाद मुआवजे की मात्रा ठीक से निर्धारित नहीं की गई है। बल्कि यह कहा गया है कि उक्त तथ्य पर बाद में अलग कार्यवाही में निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि पुनर्ग्रहण नोटिस की प्राप्ति के एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, विवाद में संपत्ति पर उत्तरदाताओं-वादी का कब्ज़ा अनधिकृत हो गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी कानून के अनुसार आगे बढ़ रहा है और नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवादी-वादी को बेदखल करने के लिए 1971 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बिक्री विलेख में प्रवेश, पूर्व। डीआई, उत्तरदाताओं-वादीगणों पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं-वादीगणों के विक्रेताओं को उनके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने की अनुमति देते समय संपदा अधिकारी द्वारा दबाव और दबाव के तहत आवेदन किया गया था। आगे तर्क दिया गया है कि हालांकि, यह साबित करना अपीलकर्ता-प्रतिवादी का काम है कि विवाद में भूमि जी.जी.ओ. के तहत "पुराने अनुदान" शर्तों के आधार पर थी। संख्या 179 और, हालांकि, वे उक्त तथ्य को साबित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने 1968 के आरएसए संख्या 1350 में भारत संघ बनाम दीवान चंद पशवारिया आदि पर भी भरोसा जताया है, जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा 6 मार्च, 1980 को दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अप्रैल, 1996 को पारित निर्णय भी दिया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील खारिज करना। भारत संघ और अन्य बनाम श्रीमती हरदर्शन साही पर भी भरोसा किया गया है, इस न्यायालय द्वारा 1973 के एलपीए संख्या 771 में दिए गए निर्णय और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 408 का ।975 दिनांक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 22 जुलाई, 1976, -जिसके द्वारा विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति दी गई। उन्होंने भारत सरकार के अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और अन्य के माध्यम से भगवती देवी बनाम भारत के राष्ट्रपति, (43) और सिविल अपील संख्या 1944 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा जताया है। 1975, 12 मई, 1994 को भारत संघ और अन्य बनाम बजरंग प्रसाद सिंगल (डीड) में एल.आर. द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। उन्होंने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम

तेजिंदर मोहन सिंह लिब्रहान और अन्य, 2006 के आरएसए नंबर 3 824 में 9 नवंबर, 2006 को पारित मामले पर भी भरोसा जताया है।

(51) उन्होंने इस बिंदु पर भी बहुत जोर दिया है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया नोटिस उत्तरदाताओं-वादी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना है और इसलिए, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ठीक ही माना है कि इसे कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। इस बिंदु पर उन्होंने नगरपालिका समिति, होशियारपुर बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, भजन कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, नॉर्दर्न इंडियन ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, पर भरोसा जताया है। सुरेश चंद्र नन्होरी बनाम राजेंद्र रजक और अन्य, चरण दास बनाम नगरपालिका समिति, समाना और अन्य, और हरियाणा राज्य बनाम राम किशन और अन्य। वर्तमान मामले में प्रतिवादी-वादी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहाली नोटिस को अवैध और शून्य घोषित कराने के लिए घोषणा की डिक्री लेने के लिए साफ हाथों से अदालत में नहीं आए हैं। एक अस्पष्ट दलील दी गई है कि प्रतिवादी-वादी विवाद में परिसर के मालिक हैं। यहां तक कि प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर लिखित बयान की प्रतिकृति में भी, वही अस्पष्ट दलील दी गई है कि वे कब्जे वाले मालिक हैं, बिना यह निर्दिष्ट किए कि वे विवाद में संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनका कब्जा बरकरार है। हालाँकि, यह साबित करने के लिए कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी उस भूमि का मालिक है, जिस पर प्रतिवादी-वादी के स्वामित्व वाली संरचना खड़ी है, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने बिक्री विलेख की प्रतिलिपि रिकॉर्ड पर रखी है, उदाहरण के लिए। डीआई, जिसे पिछले मालिकों द्वारा प्रतिवादी-वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उक्त विलेख पर वर्तमान प्रतिवादी-वादी सहित दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। वीडियो पूर्व. डीआई, विवादग्रस्त संपत्ति के साथ-साथ देहरादून में स्थित कुछ अन्य संपत्ति पिछले मालिकों, अर्थात् बृज भूषण लाल और गोपी नाथ उर्फ गोपाल कृष्ण द्वारा वर्तमान प्रतिवादी-वादी को बेची गई थी। विक्रय विलेख में, विवादित संपत्ति को बंगला नंबर 102, मॉल, अंबाला कैंट के रूप में वर्णित किया गया है, उसी की सीमाएं दी गई हैं। विक्रय पत्र के प्रथम पृष्ठ पर उदा. डीआई, इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:-

"...उक्त बंगला नंबर 102 से संबंधित भूमि, पेड़ों सहित, भारत संघ (रक्षा मंत्रालय) की संपत्ति है और उक्त मालिकों द्वारा "ओल्ड ग्रांट" के रूप में रखी गई है।

विक्रय पत्र के बाद के भाग में इसे पुनः इस प्रकार लिखा गया है

“विक्रेताओं ने खुद को संतुष्ट कर लिया है कि अंबाला कैंट में बंगला नंबर 102 के नीचे की जमीन। यह एक 'पुराना अनुदान' है और विक्रेताओं को इसके हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं है। विक्रेताओं ने उक्त विक्रेताओं के पक्ष में स्थानांतरण की मंजूरी के लिए आवेदन किया है और अंबाला कैंट में उक्त बंगला नंबर 102 के हस्तांतरण की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट बिक्री विलेख की प्रति सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है। और हस्तांतरण की मंजूरी सैन्य संपदा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर ली गई है - मेमो संख्या बीसी.9/218/ए/एल 1, दिनांक 24 अप्रैल, 1962 के माध्यम से। विक्रेताओं ने भी विक्रेताओं को आश्वासन दिया है और बाद में वे इस बात पर सहमत हुए थे कि भूमि अम्बाला कैंट में बंगला नंबर 102 के नीचे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह भारत संघ, रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है, जिसमें पेड़ भी शामिल हैं।

इसलिए, पूर्वोक्त प्रवेश के मद्देनजर। डीआई, जो इस बिंदु पर सबसे अच्छा सबूत है, अब यह कहना प्रतिवादी-वादी के मुंह में झूठ है कि भारत संघ को विवाद में संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है और यह पुराने अनुदान के रूप में उनके कब्जे में नहीं है। नियम और यह जी.ओ.जी. के नियमों और शर्तों द्वारा शासित नहीं है। क्रमांक 179, दिनांक 12 सितम्बर, 1836.

(54) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 21 के तहत, स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के प्रासंगिक टुकड़े के रूप में रखा जाता है। उक्त स्वीकारोक्ति को स्पष्ट करना प्रतिवादी-वादी का काम था। हालाँकि, उन्होंने उक्त प्रवेश के संबंध में अपने मुकदमे में कोई दलील नहीं दी है। बल्कि, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उन्होंने वादपत्र और प्रतिकृति में उक्त विक्रय पत्र के बारे में उल्लेख तक नहीं किया था। इसी तरह के तथ्यों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चित्रा कुमारी के मामले (सुप्रा) में निम्नानुसार टिप्पणी की-

(55) उनका कहना है कि सुरेंद्र कुमार वकील के मामले (सुप्रा) में ये मामले पूरी तरह से इस न्यायालय के अधिकार द्वारा कवर किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वीकारोक्ति एक मजबूत सबूत है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के आधार पर प्रासंगिक और स्वीकार्य है। उनका कहना है कि ऐसा स्वीकारोक्ति तब तक बाध्यकारी होगी जब तक कि वह इस तरह के स्वीकारोक्ति को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हो जाते। उनका कहना है कि अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या यहां तक कि यह भी कहा है कि प्रवेश जबरदस्ती या मजबूरी के तहत दिया गया था। उनका कहना है कि वकील पहली बार एसएलपी के दौरान बहस में अपने मुवक्किलों की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। उनका कहना है कि अपीलकर्ताओं के पास कोई मामला नहीं है और अपील खारिज कर दी जानी चाहिए।

हमने प्रतिद्वंद्वी अधीनता पर विचार किया है। हमारी राय में श्री रोहतगी बिल्कुल सही हैं। श्री अंध्यारुजिना के ग्राहकों के लिए विपरीत रुख अपनाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। श्री योगेश्वर

प्रसाद के मुवक्किलों के पास नीचे सभी न्यायालयों में खोए हुए तथ्य हैं। किसी अन्य मामले में देर से दिए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नोटिस का जहां तक इन अपीलों का संबंध है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। अपील में या उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिकाओं में पहली बार अप्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करने और उन पर भरोसा करने की कोशिश की निंदा की जानी चाहिए।

(55) इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि बिक्री विलेख पूर्व में उत्तरदाताओं-वादी की ओर से उपरोक्त स्वीकारोक्ति के मद्देनजर। डीआई, जी.जी.ओ. के सामान्य आदेश के अनुसार, जिस आधार पर उन्हें संपत्ति का कब्ज़ा मिला, वह भारत सरकार के स्वामित्व में नहीं है या वह कब्ज़ा "पुरानी अनुदान" शर्तों पर नहीं है। क्रमांक 179, दिनांक 12 सितम्बर, 1836. प्रतिवादी-वादी ने अपने विक्रेताओं के स्थान पर कदम रखा है। विक्रेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विवादित इमारत के नीचे की भूमि भारत संघ की है और वे "पुराने अनुदान" शर्तों पर उस पर कब्ज़ा कर रहे थे। उत्तरदाताओं-वादी के विक्रेता केवल उन्हीं अधिकारों को हस्तांतरित कर सकते थे जो विवादग्रस्त संपत्ति में उनके पास थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सुपर स्ट्रक्चर पर उनका ही अधिकार है और जमीन भारत सरकार की है. इसलिए, बिक्री विलेख, Ex.D। के माध्यम से, केवल भवन का स्वामित्व प्रतिवादी-वादी के पक्ष में स्थानांतरित किया गया है, न कि भूमि, क्योंकि वे भूमि के मालिक नहीं थे क्योंकि भूमि का मालिक भारत संघ है। सुरेंद्र कुमार वकील के मामले (सुप्रा) में, इसी तरह का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। वह मामला सागर छावनी क्षेत्र स्थित बंगले का था. उक्त बंगला 1927 में एम और उसकी पत्नी ने डी से खरीदा था। बिक्री विलेख की शर्तों ने उक्त संपत्ति पर डी के अधिकारों की प्रकृति का खुलासा नहीं किया। एम, जो सामान्य भूमि रजिस्टर में दर्ज अधिभोग-धारक था, की वर्ष 1972 में मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों, जिनके नाम परिवर्तित नहीं हुए थे, ने चार पंजीकृत बिक्री कार्यों द्वारा उत्तरदाताओं के पक्ष में बंगले सहित पूरी संपत्ति बेच दी। एक एस ने विक्रेताओं के साथ-साथ विक्रेता दोनों से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त की और इसके संबंध में सभी कार्यवाही की, और सैन्य संपदा अधिकारी से अनुरोध किया कि बंगले को खरीददारों के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सैन्य संपदा अधिकारी ने विक्रेताओं के साथ-साथ विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि उक्त क्षेत्र एम के नाम पर "ओल्ड ग्रांट" शर्तों पर रखा गया था और विक्रेताओं ने पूर्व प्राप्त किए बिना, पूरी भूमि को चार भागों में विभाजित कर दिया। अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी, जिस पर साइट आयोजित की गई थी और खरीददारों के पक्ष में बिक्री भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना और अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में थी, जो कि होगी साइट को फिर से शुरू करने के लिए कार्रवाई करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि ऐसे कार्यकाल वर्ष 1836 में गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा जारी आदेश संख्या 179 की शर्तों के अनुसार दिए गए थे, और जी.जी.ओ. में निहित नियम। छावनी

क्षेत्रों में स्थित भूमि के अनुदान के संबंध में 1836 की संख्या 179 छावनी क्षेत्रों में भूमि के अनुदान और पुनर्ग्रहण के तरीके को निर्धारित करने वाली स्व-निहित प्रक्रिया है, जो यह प्रावधान करती है कि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा और भूमि को बेचा नहीं जा सकता है। अनुदान प्राप्तकर्ता और उस पर स्थित एकमात्र घर या संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है और यहां तक कि ऐसे हस्तांतरणों के लिए स्टेशन के कमांडिंग अधिकारी की सहमति की आवश्यकता होगी जब स्थानांतरण किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो सेना से संबंधित नहीं है और इसलिए, यह माना गया कि "के संबंध में" पुराना अनुदान'' कार्यकाल के दौरान सरकार भूमि के पुनःग्रहण का अधिकार बरकरार रखती है। यह भी माना गया कि अनुदान की शर्तें 1836 के गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल के आदेश संख्या 179 के तहत वैधानिक रूप से विनियमित हैं और छावनी क्षेत्रों में भूमि का प्रशासन छावनी अधिनियम, 1924 और छावनी भूमि प्रशासन द्वारा आगे विनियमित किया जाता है। 1925 के नियम। यह भी देखा गया है कि 1836 के विनियम स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि छावनी क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल उस भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार दिया जा सकता है जो निर्धारित तरीके से सरकार द्वारा फिर से शुरू करने में सक्षम है। वहाँ से बाहर और. इसलिए, यह माना गया कि छावनी क्षेत्र में भूमि एम के पास केवल एक कब्जेदार/लाइसेंसधारी के रूप में थी, जिसका लाइसेंस अनुदान के तहत और कानून के तहत लाइसेंसकर्ता की खुशी पर रद्द किया जा सकता था। उस मामले में भी यह तर्क उठाया गया था कि चूंकि अपीलकर्ताओं, यानी, भारत संघ द्वारा वास्तविक पुराने अनुदान को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि पुराना अनुदान गवर्नर जनरल के 1836 के आदेश संख्या 179 द्वारा शासित नहीं था। -इन-काउंसिल और हालांकि, उक्त याचिका स्वीकार नहीं की गई। भारत संघ बनाम पुरूषोत्तम दास टंडन (50) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पिछला निर्णय भी प्रतिष्ठित था। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं-

श्री राज सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने छावनी क्षेत्रों में स्थित भूमि के अनुदान के संबंध में 1836 के आदेश संख्या 179 में निहित विनियमों की जांच की और माना कि विनियम स्वयं- थे। इसमें छावनी क्षेत्रों में भूमि के अनुदान और पुनःग्रहण के तरीके को निर्धारित करने का प्रावधान शामिल था। यह माना गया कि याचिकाकर्ता उक्त विनियमों के तहत भूमि का महज एक कब्जाधारी है, वह एक लाइसेंसधारी की स्थिति में था जिसका लाइसेंस अनुदान के तहत और कानून के तहत लाइसेंसकर्ता की मर्जी से रद्द किया जा सकता था। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय को इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम टोक चंद मामले में 5 जनवरी के अपने फैसले और आदेश द्वारा अनुमोदित किया था। 1999 एस.आर. भरूचा और वी.एन. द्वारा पारित। खरे, जे.जे. 14. हालांकि, प्रतिवादी का तर्क है कि चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा वास्तविक पुराने अनुदान को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत

नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि भूमि पुराने अनुदान के आधार पर मुखर्जी द्वारा आयोजित की गई थी, अपीलकर्ताओं द्वारा साबित नहीं किया गया है। यह प्रस्तुतिकरण हमें आकर्षित नहीं करता है। प्रतिवादियों ने भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। यदि इस भूमि के संबंध में किसी भी समय राज्य/सैन्य संपदा अधिकारी द्वारा मुखर्जी या उनके पूर्ववर्ती के पक्ष में कोई हस्तांतरण निष्पादित किया गया था, तो हस्तांतरण उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया गया था/किया गया था या शीर्षक में उनका उत्तराधिकारी। यदि उक्त भूमि के संबंध में मुखर्जी या उनके पूर्ववर्ती के पक्ष में पट्टा दिया गया था, तो पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारी को उनके पक्ष में पट्टा विलेख प्रस्तुत करना चाहिए था। अनुदान प्राप्तकर्ता के पक्ष में कोई भी अनुदान सामान्यतः अनुदान प्राप्तकर्ता के कब्जे में होगा। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने विचाराधीन भूमि से संबंधित कोई स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने केवल दुबे से मुखर्जी को बिक्री के दस्तावेज और मुखर्जी के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों से क्रय उत्तरदाताओं के पक्ष में चार बिक्री पत्र प्रस्तुत किए हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ में विक्रेता के पास मौजूद भूमि पर अधिकारों की प्रकृति का स्पष्ट वर्णन नहीं है। चित्रा कुमारी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के फैसले में, जो अंबाला छावनी में स्थित एक बंगले के संबंध में था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार वकील के मामले (सुप्रा) पर भरोसा जताया। उस मामले में यह भी देखा गया कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि भूमि "पुरानी अनुदान" शर्तों पर थी, तो यह तर्क देना अप्रासंगिक है कि यह नहीं दिखाया गया है कि अंबाला बंगाल सेना के अधीन था और जब भी निर्णय लिया जाएगा तब वही होगा साक्ष्य के आधार पर, न्यायालय ने माना है कि भूमि "पुरानी अनुदान" शर्तों पर है।

(58) जहां तक दीवान चंद पश्वारिया आदि के मामले (सुप्रा) का सवाल है, यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, उस मामले में भी, यह माना गया कि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि सरकार को उक्त आदेश के तहत दी गई भूमि को फिर से शुरू करने का अधिकार है और, हालांकि, यह देखा गया कि उक्त आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उसे कब्ज़ा लेने के लिए अधिकृत करता हो। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता पुनर्ग्रहण आदेश के बाद कब्ज़ा छोड़ने में विफल रहता है तो कार्यकारी कार्रवाई द्वारा।

(59) हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-प्रतिवादी कानून के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उत्तरदाताओं-वादी द्वारा कब्जा देने में विफल रहने के बाद, बहाली के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, 1971 अधिनियम के तहत सैन्य संपदा अधिकारी के समक्ष उत्तरदाताओं-वादी को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू की गई है। इसलिए, उक्त निर्णय प्रतिवादियों-वादीगणों के लिए कोई मददगार नहीं है।

तेजिंदर मोहन सिंह लिबक्रहान के मामले (सुप्रा) में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष थे कि वादी यह साबित करने में सक्षम थे कि वे विवाद में संपत्ति के मालिक थे और यह साबित नहीं किया जा सकता है कि संपत्ति का स्वामित्व था पिछले मालिकों को "ओल्ड ग्रांट" शब्द के रूप में रखा गया था, जबकि, वर्तमान मामले में, बिक्री विलेख Ex.D1 में पुनरावृत्ति के मद्देनजर यह एक तथ्य के रूप में साबित हुआ है कि संपत्ति को पिछले मालिकों द्वारा "ओल्ड ग्रांट" के रूप में रखा गया था और इसलिए , उक्त निर्णय भी उत्तरदाताओं-वादीगणों के लिए कोई सहायता नहीं है।

(61) अब तक मुख्य बिंदु, जिस पर वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर की गई है कि क्या विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उत्तरदाताओं-वादी के मुकदमे को डिक्री करने में सही था, यहां तक कि यह मानते हुए कि वे विवाद में संपत्ति के कब्जे में हैं "ओल्ड ग्रांट" की शर्तें और यह कि बहाली नोटिस अवैध और शून्य है क्योंकि इसे उत्तरदाताओं-वादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किया गया है, टेक चंद के मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा उक्त बिंदु का निपटारा किया गया है। (सुप्रा)। वह भी अंबाला छावनी स्थित बंगले से संबंधित मामला था और जीजीओ के विनियमन 6 के तहत जारी किया गया नोटिस था। संख्या 179, दिनांक 12 सितंबर, 1836 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नोटिस जारी करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और यहां तक कि सुपर स्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए मुआवजा भी वादी को कोई अवसर दिए बिना निर्धारित किया गया था और हालांकि, उक्त याचिका इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार स्वीकार नहीं किया गया था-

11. उपरोक्त के मद्देनजर, इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है कि केंद्र सरकार विनियमन 6 के प्रावधानों को लागू करने के अपने अधिकार में नहीं थी। याचिकाकर्ताओं के साथ अनुदान की शर्तों के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए, जिसका पालन करने के लिए वे उस पर अधिरचना के निर्माण के उद्देश्य से भूमि का अनुदान स्वीकार करते समय सहमत हुए थे, जो अब साइट के साथ फिर से शुरू हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने अतीत में और याचिका के पैरा 23 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनुदान भूमि पर अधिरचना प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था। यह अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी गई कुछ रियायत के समान है और ऐसी रियायत का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और यदि याचिकाकर्ताओं को वह रियायत नहीं दी गई है, तो केंद्र सरकार की उस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जब कोई अपना दावा पेश करता है, तो वह अपने दावे को उसी तक सीमित रखने के लिए प्रतिबंधित होता है जिसका वह कानून में हकदार है। अब हम याचिकाकर्ता के इस तर्क की जांच कर रहे हैं कि नोटिस जारी करने से पहले और मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने से पहले, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इस विवाद के लिए इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले से

समर्थन मांगा, जिसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रीमती हर दर्शन साही के रूप में रिपोर्ट किया गया और निम्नलिखित टिप्पणियों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया-

"श्री कुलदीप सिंह का इस आशय का तर्क कि अनुदान में एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में अनुदान प्राप्तकर्ता को उसके अनुदान के किसी भी हिस्से को फिर से शुरू करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संतुष्ट करने का कोई सवाल नहीं हो सकता है उठता है, पूरी तरह से योग्यता के बिना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हमेशा वहां कदम रखेंगे जहां किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार शामिल हैं या जहां कुछ अर्ध-न्यायिक और न्यायिक कार्यों का प्रयोग किया जाना है, जब तक कि उनमें से किसी भी सिद्धांत के आवेदन को प्रासंगिक कानून या अनुदान द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा जाता है। इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ऐसा कोई बहिष्कार नहीं है। इसलिए, उन सिद्धांतों को अनुदान के एक हिस्से को फिर से शुरू करने के पी प्रश्न और मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के प्रश्न, जिसके लिए प्रतिवादी हकदार है, दोनों पर लागू होना चाहिए। श्रीमती हरदर्शन साही के मामले (सुप्रा) का अनुपात स्वयं उत्तरदाताओं की ओर से, पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण का विरोध करने के लिए, हमारे सामने रखा गया है। उत्तरदाताओं की ओर से मुख्य न्यायाधीश नरूला की निम्नलिखित टिप्पणियों पर जोर दिया गया है, जिन्होंने उपरोक्त मामले में बेंच के लिए इस प्रकार बात की थी: - "मैं चैंबर्स में विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से भी पूरी तरह सहमत हूं कि चीजें होतीं यदि अनुदान की विषय-वस्तु बनाने वाले पूरे प्लॉट को फिर से शुरू किया जाए तो यह पूरी तरह से अलग होगा। उस स्थिति में, अनुदान को फिर से शुरू करने के अनुदानदाता के पूर्ण अधिकार को ध्यान में रखते हुए, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा बहाली के खिलाफ कोई कारण नहीं दिखाया जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामले में चीजें काफी हद तक भिन्न होती हैं, जहां सरकार अनुदान की विषय-वस्तु वाली भूमि के एक हिस्से को फिर से हासिल करना चाहती है। यह प्रदर्शित करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है कि एक भूखंड, जिस पर एक ही स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर एक बंगला बनाया गया है, के बिल्कुल समान क्षेत्र को फिर से शुरू करने से अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए बहुत फर्क पड़ सकता है, जिसके पास शेष भूमि जा रही है। छोड़ दिया जाना चाहिए, हालाँकि इससे सरकार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक सड़क से सटे या अन्यथा भूमि के एक विशेष क्षेत्र के लिए उसकी आवश्यकता का संबंध है। ऐसी स्थिति में मुख्य बात यह है कि अनुदान के एक हिस्से को फिर से शुरू करने के बाद शेष भूमि को रखने के अनुदान प्राप्तकर्ता के नागरिक अधिकार क्षेत्र के चयन से गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाते हैं, जो एक घटना में व्यावहारिक रूप से शेष अनुदान को भी नष्ट कर सकता है और दूसरे में घटना, यह न तो उसे बिल्कुल प्रभावित कर सकती है या नगण्य रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में मुझे यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक बार सामने आएंगे और केंद्र सरकार को प्रतिवादी की

आपत्तियों और/या वैकल्पिक सुझावों को सहन करने की आवश्यकता होगी और फिर अंततः यह तय करना होगा कि संपत्ति का कौन सा हिस्सा वे लेंगे। लेना पसंद है. बेशक, प्रतिवादी को सुनने के बाद सरकार का निर्णय किसी भी तर्क अपील या जांच के अधीन नहीं है। श्री सुदर्शन साहू मामले (एआईआर 1975 पंजाब और हरियाणा 228) (सुप्रा) में तथ्य यह थे कि अनुदान भूमि का केवल एक हिस्सा था इसे फिर से शुरू करने की मांग की गई और यही कारण है कि इस न्यायालय ने माना कि फिर से शुरू करने का नोटिस जारी करने से पहले, अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है कि संपूर्ण अनुदान को फिर से शुरू करने की मांग की गई है और इसलिए, श्रीमती हरदर्शन साही के मामले (सुप्रा) में परिकल्पित किसी भी अवसर को प्रदान करने का सवाल ही नहीं उठता है। मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के संबंध में एक अवसर प्रदान करने के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि अनुदान भूमि और उसके सुपरस्ट्रक्चर को फिर से शुरू करने की कार्रवाई सुपरस्ट्रक्चर के मूल्य के पूर्व भुगतान में सशर्त नहीं है। यह एक दायित्व है जो पुनः आरंभ करने की कार्रवाई से उत्पन्न होता है। अनुदान प्राप्तकर्ता की स्थिति लाइसेंस की है, एक बार लाइसेंस फिर से शुरू हो जाने पर, उसकी स्थिति एक अतिचारी की हो जाती है और वह फिर से शुरू की गई संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, जिसके लिए वह हकदार होगा यदि यह माना जाता है कि लाइसेंस के मूल्य का भुगतान किया जाता है। अनुदान की बहाली की स्थिति में अनुदान भूमि पर अधिरचना, उसकी बहाली से पहले की शर्त होगी और मूल्य का निर्धारण अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद किया जाएगा।

14. हम प्रतिवादियों के वकील के साथ पूरी तरह से बहस करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, जब उन्होंने भगवती देवी बनाम भारत के राष्ट्रपति 1972 ऑल एलजे 382 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपात के आधार पर यह प्रचार किया कि यदि मुआवजे की पेशकश अनुदान प्राप्तकर्ता को स्वीकार्य नहीं थी, वह नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री को हटा सकता था और उत्तरदाताओं को साइट का खाली कब्जा दे सकता था।

15. अनुदान अधिनियम का विनियमन 6 अनुदान को फिर से शुरू करने के लिए सरकार पर दो शर्तें लगाता है, यानी, (1) कि वह एक महीने का नोटिस देगी और (2) कि वह निर्माण की अनुमति प्राप्त इमारत के मूल्य का भुगतान करेगी। अनुदान भूमि पर. इस विनियमन की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए कि यह न तो अनुदान को फिर से शुरू करने के उक्त प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य को विफल करता है, जब भी अनुदानकर्ता इसे आवश्यक समझता है और न ही यह अनुदान प्राप्तकर्ता के कानून के अनुसार पूर्ण मूल्य प्राप्त करने के अधिकार को खतरे में डालता है। जिस भवन का निर्माण उसे अनुदान भूमि पर करने की अनुमति दी गई थी। जब ऐसा समझा जाता है, तो सुपरस्ट्रक्चर के मूल्य के भुगतान के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से हमारे विचार में "इसे छोड़ दें" या "इसे ले लें" का चरम विवाद, पारित नहीं हो

सकता है। अत्यंत सम्मान के साथ, हम स्वयं को भगवती देवी के मामले 1972 यूएलजे 382 (सुप्रा) में प्रतिपादित दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ पाते हैं।

हमारा विचार है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कि बहाली के आदेश के संचालन के लिए भवन के मूल्य के भुगतान का इंतजार नहीं किया जा सकता है। बहाली का आदेश नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख पर लागू हो जाता है। इसके बाद, अनुदान प्राप्तकर्ता भी इमारत में रहने की कोशिश करता है, तो वह ऐसा अतिक्रमणकर्ता के रूप में करता है न कि अनुदान प्राप्तकर्ता या लाइसेंसधारी के रूप में और उससे कानून के अनुसार निपटा जा सकता है। हालाँकि, यह उत्तरदाताओं पर निर्भर होगा कि वे फिर से शुरू की गई इमारत के मूल्य की मात्रा के निर्धारण के संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करें। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी बात सुनने के बाद निर्धारित मुआवजे की मात्रा को स्वीकार नहीं करता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता मुआवजे की अपर्याप्तता को सामान्य सिविल न्यायालय में चुनौती दे सकता है और जो वह मानता है उसकी वसूली की मांग कर सकता है। दोबारा शुरू की गई इमारत के लिए उचित और कानूनी मुआवजा दिया जाए।

उक्त मामले में, माननीय डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला-

"(i) कि भवन और उसके नीचे की साइट का पुनरुद्धार विनियम 6 के तहत एक याचिकाकर्ता की समाप्ति की तारीख पर चालू हो गया, क्योंकि भवन का पुनरुद्धार भवन के मूल्य के पूर्व भुगतान पर निर्भर नहीं है ;

(ii) यह उत्तरदाताओं पर निर्भर था कि वे पुनः शुरू की गई इमारत के मूल्य की मात्रा निर्धारित करने के समय याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करें, और

(iii) चूंकि याचिकाकर्ताओं को फिर से शुरू की गई इमारत के लिए मुआवजे की मात्रा के संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे मुआवजे की मात्रा के आकलन के संबंध में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दें। फिर से शुरू की गई इमारत के लिए और उसके बाद उक्त इमारत के लिए मुआवजे की मात्रा तय करें।"

वर्तमान मामले के तथ्य टेक चंद के मामले (सुप्रा) के समान हैं। प्रतिवादी-वादी के साथ सख्ती से और जीजीओ में उल्लिखित अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। संख्या 179, दिनांक 12 सितंबर, 1836। वर्तमान प्रतिवादी-वादी ने अपने पूर्ववर्तियों के स्थान पर कदम रखा है। उक्त आदेश के विनियम 6 के अनुसार, भारत संघ को बिना कोई कारण बताए साइट को फिर से शुरू करने का अधिकार है और एकमात्र आवश्यकता एक महीने का नोटिस देना है, जो वर्तमान मामले में दिया गया है। इस मामले में हरदर्शन साही के मामले (सुप्रा) पर भी चर्चा की गई है, जिस पर प्रतिवादी-वादी के वकील पर भरोसा

किया गया है। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि मुआवजे के सवाल का निर्धारण करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, यह माना गया कि अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था और हालांकि, यह माना गया कि बहाली के आदेश के संचालन के लिए भुगतान का इंतजार नहीं किया जा सकता है। भवन का मूल्य और बहाली का आदेश नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख पर लागू होता है और यह सरकार पर निर्भर होगा कि वह इस संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करे। पुनः आरंभ किए गए भवन के मूल्य की मात्रा का निर्धारण करने के लिए। आगे यह माना गया कि अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा मुआवजे की मात्रा स्वीकार नहीं करने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी सुनवाई के बाद निर्धारित किया जा सकता है और यह अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए सामान्य सिविल न्यायालय में मुआवजे की अपर्याप्तता को चुनौती देने के लिए खुला होगा और दोबारा शुरू की गई इमारत के लिए उचित और कानूनी मुआवजे की मांग करें।

(64) यह मुद्दा राज सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी विचार के लिए आया था, (51) और यह देखा गया कि मुआवजे की मात्रा पर स्वतंत्र कार्यवाही में विचार करना होगा भूतपूर्व अनुदानग्राही और सरकार। '

(65) माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ और अन्य बनाम हरीश चंद आनंद, (52) ने राज सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी दे दी।

हरीश चंद आनंद के मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि "क्या अनुदान प्राप्तकर्ता का एकमात्र अधिकार मुआवजे का दावा करना है और क्या सरकार एक महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय कब्जा ले सकती है" गवर्नर जनरल के आदेश संख्या 179. दिनांक 12 सितंबर, 1836 का?" और इसे इस प्रकार देखा गया-

"2. संविधान के अनुच्छेद 133(1) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के मद्देनजर, सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 की धारा 3 के तहत पूर्व निर्धारण के बिना दी गई भूमि को फिर से शुरू करने का हकदार है। संरचना के लिए राशि। हालांकि प्रतिवादी को सेवा दे दी गई है, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं हुआ है। हमने अपीलकर्ता के लिए वकील की सहायता ली है और हमने राज सिंह बनाम मामले में रिपोर्ट किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया है। भारत संघ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में भगवती देवी बनाम भारत के राष्ट्रपति की रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर इस मामले में डिवीजन बेंच ने भरोसा किया और उसका पालन करते हुए कहा कि यह एक शर्त है कि राज्य को नोटिस देना चाहिए। प्रतिवादी, मुआवजे का निर्धारण करेगा और फिर प्रतिवादी को दिए गए उचित मुआवजे को

फिर से शुरू करेगा। इसलिए, सवाल यह है कि क्या यह हल्की सरकार के लिए एक शर्त है कि वह मुआवजे और उसके भुगतान के निर्धारण के बाद या उसके जारी होने पर ही भूमि को फिर से शुरू करे। अनुदान के तहत आवश्यक सूचना और उसकी समाप्ति पर। विवाद की सराहना करने के लिए, अनुदान के प्रावधानों को देखना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 3 के तहत. गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल ने शक्ति का प्रयोग किया और प्रतिवादी को सरकारी भूमि पर संरचना खड़ी करने का लाइसेंस दिया। अनुदान की शर्तें हैं:

'निम्नलिखित शर्तों के अलावा कोई आधार नहीं दिया जाएगा, जिसकी सदस्यता प्रत्येक अनुदान प्राप्तकर्ता के साथ-साथ उन लोगों को भी देनी होगी जिन्हें बाद में उसका अनुदान हस्तांतरित किया जा सकता है। सबसे पहले, सरकार को किसी भी समय एक महीने का नोटिस देने और ऐसी इमारतों के मूल्य का भुगतान करने पर फिर से शुरू करने की शक्ति बरकरार रखनी होगी, जिन्हें खड़ा करने के लिए अधिकृत किया गया हो। अन्य धाराएं इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसलिए, उन्हें छोड़ दिया गया है।

3. 1836 के आदेश संख्या 179 में, गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल ने गवर्नर जनरल को तब तक लागू अधिकृत आदेशों को रद्द करने और उनके स्थान पर नियमों द्वारा प्रतिस्थापित करने का अधिकार देने वाला विनियमन जारी किया था। 1836 के आदेश संख्या 179 के नियम गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए वैधानिक नियम हैं। अनुदान के लिए अनुबंध स्पष्ट रूप से सरकार को किसी भी समय फिर से शुरू करने की अपनी शक्ति बनाए रखने का अधिकार देता है। मिसाल की शर्तें हैं- एक महीने का नोटिस जारी करना और ऐसी इमारत के मूल्य का भुगतान करना, जिसे खड़ा करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले भवन के मूल्य के निर्धारण के तरीके के प्रश्न को खुला छोड़ दिया है। भगवती देवी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पैरा 7 में कहा था कि हालांकि सरकार भूमि को फिर से शुरू करने की हकदार है, लेकिन अनुदान प्राप्तकर्ता भूमि के मूल्य के निर्धारण में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व अवसर का हकदार है। भवन और ऐसी इमारत के मूल्य का भुगतान राज्य द्वारा फिर से शुरू किया जाएगा।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश स्थायी आदेश संख्या 241 में दिए गए थे, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें सैन्य अभियंता को उस इमारत के मूल्य का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था जिसे फिर से शुरू किया गया था। पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी को राशि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा। हम इस अपील में मूल्यांकन की पद्धति के बारे में चिंतित नहीं हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आदेश संख्या 241 हालांकि पूर्ववर्ती

लाइसेंसधारी को पूर्व नोटिस जारी करने पर विचार नहीं करता है जिसका लाइसेंस अनुदान के खंड । के तहत निर्धारित किया गया है, वास्तविक राशि के निर्धारण से पहले, पूर्ववर्ती अनुदान प्राप्तकर्ता नोटिस का हकदार है, इसलिए कि अनुदान प्राप्तकर्ता भवन का मूल्य निर्धारित करने और उसके भुगतान के लिए सभी प्रासंगिक सामग्री सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह देखा गया है कि पहली बार में मुआवजा निर्धारित करने के बाद उसका भुगतान करने का अवसर देना और फिर संपत्ति को फिर से शुरू करना कोई पूर्व शर्त नहीं है। एक शर्त यह है कि एक महीने का नोटिस जारी किया जाता है और उसकी समाप्ति पर सरकार भूमि को फिर से शुरू करने की हकदार होती है। अवसर देने के बाद संबंधित प्रावधान के तहत आवश्यक राशि का निर्धारण किया जाना है और जो उसके बाद किया जा सकता है। आख़िरकार। संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए फिर से शुरू किया जाएगा और निर्मित भवन के मूल्य का निर्धारण एक मंत्रिस्तरीय कार्य है और उसका भुगतान परिणामी परिणाम है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा और यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तर्क को प्रभावी बनाया जाता है। यह सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर देगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण योजना के अनुरूप है और व्यावहारिक और यथार्थवादी प्रतीत होता है। इसलिए, उच्च न्यायालय अपने इस निष्कर्ष पर सही नहीं था कि पहली बार में इमारत के मूल्य की राशि निर्धारित करना और संपत्ति की बहाली के लिए उसका भुगतान करना एक पूर्व शर्त है।"

(67) चित्रा कुमारी के मामले (सुप्रा) में यह मुद्दा फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जो अंबाला छावनी में स्थित एक बंगले के संबंध में भी था। मैंने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर पिछले सभी निर्णयों पर चर्चा की, यानी भारत संघ बनाम पुरुषोतम दास टंडन का मामला (सुप्रा)। सुरेंद्र कुमार वकील का मामला (सुप्रा) और हरीश चंद आनंद का मामला (सुप्रा) और निम्नानुसार देखा गया-

"15 1997 की एसएलपी (सी) संख्या 22436-22437 से उत्पन्न सिविल अपील में भी अंबाला छावनी में बंगला और जमीन का मामला था। बहाली का नोटिस 30 जुलाई 1971 को दिया गया था। मुकदमा अदालत में दायर किया गया था उप-न्यायाधीश। प्रथम श्रेणी। अम्बाला। इस मुकदमे में यह तर्क दिया गया था कि यह साबित नहीं हुआ था कि भूमि पुराने अनुदान की शर्तों पर थी। यह भी आग्रह किया गया था कि पुराने अनुदान की शर्तें भूमि को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देती थीं। हालाँकि, नहीं यह साबित करने के लिए सबूत पेश किए गए कि वादी मालिक थे। वादी- अपीलकर्ता और उसके गवाहों ने यह नहीं बताया कि भूमि प्रतिवादियों की नहीं थी। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्तियों द्वारा लिखित रूप में स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड पर लाया था और प्रदर्शित किया था। भूमि पुरानी अनुदान शर्तों, जी.जी.ओ.

संख्या 179, दिनांक 12 सितंबर, 1836 और भूमि अभिलेखों के रजिस्टर पर थी। इस मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया।

इसे आगे इस प्रकार देखा गया-

"23 श्री अंध्यारुजिना ने प्रस्तुत किया कि पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दुर्गा दास सूद बनाम भारत संघ के मामले में यह विचार किया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए और जब तक बहाली का कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता। और जब तक पहले संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मुआवजा तय नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि मोहन अग्रवाल बनाम भारत संघ के मामले में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यही दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने कहा कि यही कानून प्रचलित है। उन्होंने कहा कि इस कानून के कारण ट्रायल कोर्ट ने एक आसान रास्ता निकाला और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किए जाने के संकीर्ण बिंदु पर ही उनके मुवक्किलों के मुकदमे का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके मुवक्किलों ने अपना मामला आगे नहीं बढ़ाया था या छोड़ दिया था कि भूमि पुरानी अनुदान शर्तों पर नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि ट्रायल कोर्ट ने एक आसान रास्ता अपनाया और उनके मुवक्किलों द्वारा आग्रह किए गए सभी बिंदुओं पर फैसला नहीं किया, अपीलकर्ताओं को उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि उनके मुवक्किल ट्रायल कोर्ट में सफल हो गए हैं, इसलिए उन्हें अपील दायर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष भी उनके मुवक्किल सफल हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल 1995 में, हरीश चंद मामले में, इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और राज सिंह मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने तत्कालीन कानून के आधार पर ही उनके मुवक्किल के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अदालतों ने मामले को केवल एक बिंदु पर तय करने का फैसला किया, भले ही उनके मुवक्किलों ने सभी चरणों में इस मामले को नहीं छोड़ा था कि यह पुरानी अनुदान शर्तों पर नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालतों ने अन्य पहलुओं पर निर्णय नहीं लेने का फैसला किया है।

24. श्री अंध्यारुजिना ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि जब भी यह सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज का मालिक है जिसके कब्जे में उसे दिखाया गया है, तो यह साबित करने का बोझ है कि वह मालिक नहीं है उस व्यक्ति पर है जो पुष्टि करता है कि वह मालिक नहीं है। मेरा कहना है कि अपीलकर्ता और उनके पूर्ववर्तियों का स्वामित्व पर कम से

कम 1926 से कब्जा है। उनका कहना है कि यह दिखाने का बोझ पूरी तरह से उत्तरदाताओं पर था कि वे मालिक नहीं थे। उनका मानना है कि बोझ से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका पुराने अनुदान का उत्पादन करना था। उनका कहना है कि केवल एक रजिस्टर प्रस्तुत करना जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संपत्ति पुरानी अनुदान शर्तों पर है, पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि रजिस्टर और जी.जी.ओ. की प्रति। 1836 का क्रमांक 179 द्वितीयक साक्ष्य होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के तहत वर्जित किया जाएगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि पुराना अनुदान उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि पुराना अनुदान, यदि कोई था, खो गया था या गुम हो गया था या वह उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि केवल रजिस्टर या अनुदान की शर्तों की साइक्लोस्टाइल प्रति प्रस्तुत करना कोई सबूत नहीं है।"

(68) इसलिए, मेरी उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह माना जाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बहाली नोटिस को इस आधार पर अवैध घोषित करने में अवैधता की है कि उक्त नोटिस जारी करने से पहले उत्तरदाताओं-वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और वह मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि संपत्ति प्रतिवादी-वादी द्वारा "ओल्ड ग्रांट" शर्तों पर रखी गई थी, ने नोटिस को अवैध मानने में अवैधता की है।

(69) इसलिए, कानून संख्या 1 से 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में और प्रतिवादी-वादी के खिलाफ तय किए जाते हैं।

हालाँकि, यह स्वीकृत तथ्य है कि भारत संघ की भूमि पर बनी इमारत के अधिग्रहण के कारण उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने से पहले प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि निर्माण एक अनुमेय है। एक। इसलिए, प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का अधिकार है, भले ही जी.जी.ओ. में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। संख्या 179, जैसा कि टोक चंद के मामले (सुप्रा) में इस अदालत की डिवीजन बेंच द्वारा आयोजित किया गया है।

(70) इसलिए, इस हद तक नोटिस लगाया गया है कि यह इमारत के अधिग्रहण के संबंध में देय मुआवजे को केवल रु। 64,126 को कानून की नजर में खराब कहा जा सकता है. पुनर्निर्मित भवन के मूल्य की मात्रा के निर्धारण के संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर देना प्रतिवादी-वादी का दायित्व है।

(71) मेरी उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, वर्तमान नियमित दूसरी अपील स्वीकार की जाती है। निम्न विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री को निरस्त किया जाता है। इसके

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इसे आगे इस प्रकार रखा गया है-

कि भवन और उसके नीचे की साइट का पुनः आरंभ विनियम 6' के तहत प्रतिवादी-वादी को दिए गए एक महीने के नोटिस (प्राप्ति की तारीख से) की समाप्ति की तारीख पर चालू हो गया क्योंकि भवन का पुनः आरंभ इस पर निर्भर नहीं है भवन के मूल्य का पूर्व भुगतान।

(ii) यह अपीलकर्ता-प्रतिवादी का दायित्व है कि वह दोबारा शुरू की गई इमारत की मात्रा का निर्धारण करते समय प्रतिवादी-वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे; और

(iii) चूंकि प्रतिवादी-वादी को पुनर्निर्मित भवन के लिए मुआवजे की मात्रा के संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी-वादी को अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाए। पुनः आरंभ की गई इमारत के लिए मुआवज़े का आकलन करना और उसके बाद उक्त इमारत के लिए मुआवज़े की मात्रा निर्धारित करना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा